कमल संदेश
ikf{kd i=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक

संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य

सत्यपाल

कला संपादक

धर्मेन्द्र कौशल
विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-
त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798
Qku (dk-) : +91(11) 23381428
QDI : +91(11) 23387887

पता : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003

ई–मेल
kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

विषय–सूची

'विजय दिवस रैली, कोलकाता
राज्य में भाजपा का विस्तार तृणमूल के लिए अभिशाप बना.................... 6

भाजपा के नेतृत्व में राजग की छह महीने सरकार
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने नई आशाएं और दूरदृष्टि प्रदान की....... 9

सार्क शिखर सम्मेलन : काठमांडू (नेपाल)
साथ होने से बढ़ेगी ताकत.. 12

प्रधानमंत्री की पूर्वोत्तर-यात्रा
पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र एक 'प्राकृतिक आर्थिक क्षेत्र' है................................ 14

संसद में काला धन पर बहस : लोकसभा
अरुण जेटली.. 17

वैचारिकी
एकात्म मानववाद
–दीनदयालजी उपाध्याय.. 20

लेख
'सबका साथ, सबका विकास' से अलग–थलग पड़ा पाकिस्तान
–डा. शिव शक्ति बक्सी.. 26

अटल जी के 90वां जन्मदिन पर विशेष : 25 दिसम्बर 2014
''अंधकार छंटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा''......................... 23

अन्य
दलित महापंचायत : दिल्ली... 29

जीवेम शरदः शतम्

श्री अटल बिहारी वाजपेयी
जन्म-दिवस : 25 दिसम्बर

भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, वरिष्ठ भाजपा नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी एवं डॉ. मुरली मनोहर जोशी, केन्द्रीय मंत्रीगण – श्री राजनाथ सिंह, श्री अरूण जेटली, श्रीमती सुषमा स्वराज, श्री एम वेंकैया नायडू और श्री नितिन गडकरी, राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) श्री रामलाल एवं कमल संदेश के सम्पादक श्री प्रभात झा सहित अन्य सभी नेतागण एवं कार्यकर्ता श्री अटल बिहारी वाजपेयी की दीर्घायु की कामना करते हुए अभिलाषा रखते हैं कि वे चिरकाल तक पार्टी एवं राष्ट्र का मार्गदर्शन करते रहें।

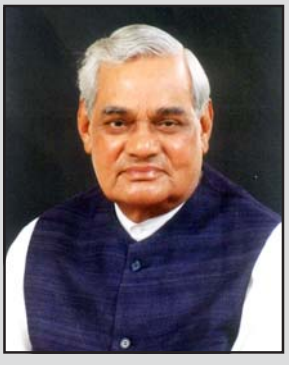

पगड़ी और टोपी

एक दिन एक व्यक्ति गांधी जी से मिलने आया। उसने अपने सिर पर बहुत बड़ी पगड़ी बांध रखी थी। उसने पूछा, 'गांधी जी, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, यदि आप आज्ञा दें तो पूछूं?' गांधी जी बोले, 'बिल्कुल, आप जरूर पूछें।' वह व्यक्ति बोला, 'आजकल हर जगह गांधी टोपी की बड़ी चर्चा है। हर दूसरा व्यक्ति गांधी टोपी लगाए इतरा कर कहता है कि मैंने गांधी टोपी पहनी है। पर मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि वह टोपी भला गांधी टोपी कैसे हो गई? आप तो टोपी पहनते ही नहीं, फिर उस टोपी को सभी गांधी टोपी क्यों कहते हैं?'

गांधी जी मुस्करा कर बोले, 'बात यह है कि मैं हर चीज का किफायत से उपयोग करने की बात कहता हूं। साथ ही मेरा यह भी मानना है कि हर वस्तु का उपयोग तब तक करना चाहिए जब तक कि वह बिल्कुल ही खराब न हो जाए। यह टोपी बहुत ही किफायती है। साथ ही इसे घर में भी बनाया जा सकता है। इसे बनाने में किसी बहुमूल्य वस्तु का उपयोग नहीं होता। इसे सीधे-सादे तरीके से बनाकर प्रयोग किया जा सकता है। मैं ऐसी वस्तुओं का हिमायती हूं। इसलिए लोगों ने इसका नाम गांधी टोपी रख दिया है।'

इस पर वह व्यक्ति बोला, 'गांधी जी, फिर आप गांधी टोपी क्यों नहीं धारण करते?' इस पर गांधी जी मुस्करा कर बोले, 'दरअसल भारत में तुम जैसे अनेक लोग पगड़ी में लगभग इक्कीस बाइस टोपी बनाने लायक कपड़ा बांध लेते हो। अब उस संतुलन को भी तो पूरा करना है। इसलिए मैं गांधी टोपी का प्रयोग नहीं करता।' गांधीजी का जवाब सुनकर वह व्यक्ति लज्जित हो गया।

संकलन : रेनू सैनी (नवभारत टाइम्स से साभार)

पाथेय

संसार के अन्य अनेक प्राचीन कहे जानेवाले देशों में उनकी पुरातन संस्कृति के दर्शन नहीं होते। उदाहरणार्थ, चीन में आज उसकी प्राचीन संस्कृति विद्यमान नहीं है, किंतु भारत में आज भी प्राचीन संस्कृति और गौरवपूर्ण परंपरा के दर्शन किए जा सकते हैं। अभी भी काफी लोगों की उस पर श्रद्धा है। किंतु यह बात दूसरी है कि वह जितनी मात्रा में चाहिए, उसका अभाव है। हमारी वर्तमान अनेक समस्याओं का भी यही मूल कारण है। भारतीय जीवन दर्शन तथा संस्कृति के आधार पर ही हम अपने राष्ट्र का वांछित विकास कर सकते हैं। इसके लिए भारतीय संस्कृति तथा आदर्शों की श्रेष्ठता पर पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास की आवश्यकता है।

- पं. दीनदयाल उपाध्याय
(उ.प्र. जनसंघ अधिवेशन, 1955)

'सुशासन दिवस' के रूप में मनेगा अटलजी का जन्मदिन

भारतीय जनता पार्टी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन 'सुशासन दिवस' के रूप में मनाने जा रही है। भाजपा जहां भी शासन में आई, चाहे केन्द्र हो अथवा राज्य, भाजपा सरकारों की पहचान सुशासन रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को इस अवसर को पार्टी के सुशासन के प्रति पुनः प्रतिबद्ध करने के लिए चुनने के लिए बहुत-बहुत बधाई। इस निर्णय की घोषणा स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भाजपा संसदीय दल की बैठक में किया तथा भाजपा सांसदों को यह दिन सुशासन के प्रतीक के तौर पर मनाने के लिये कहा। सुशासन दिवस के रूप में 25 दिसम्बर को सभी सांसदों को अपने क्षेत्र में स्वच्छ भारत अभियान एक घंटा के लिए आयोजित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर वे स्वयं अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में स्वच्छता अभियान चलायेंगे।

यह पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 90वां जन्मदिवस है। अटल जी, जैसा कि लोग उन्हें स्नेह एवं आदर से बुलाते हैं, अभी भी करोड़ों दिलों में बसे हुए हैं। संयुक्त राज्य में उनका भाषण जब पहली बार हिन्दी वहां गूंजी थी, को कौन भूला सकता है? देश को वो दिन अब भी याद है जब जनता पार्टी सरकार में विदेश मंत्री के तौर पर उन्होंने भारत के विदेश नीति को नये आयाम दिए थे। भारतीय राजनीति के एक विराट व्यक्तित्व जो उदारता एवं बड़े दिल के साथ-साथ अपने आदर्शों के लिए प्रतिबद्ध एवं मन बना लेने पर अडिग रहने वाले माने जाते रहे हैं। देश पोखरण-II विस्फोट एवं तत्पश्चात लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध अभी तक भूला नहीं है। गौरव से मस्तक ऊंचा किए भारत इन प्रतिबंधों के सामने डटकर खड़ा रहा और प्रतिबंधों के दंश पर अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से काबू पाने में सफल रहा। उनके नेतृत्व में भारत कारगिल युद्ध में विजयी रहा। दोस्ती में वे पाकिस्तान के साथ उदार रहे परन्तु युद्ध में कठोर। देश ने उनका कड़ा रूख संसद पर हुए आतंकी हमले के दौरान देखा। अटल जी के व्यक्तित्व ने भारतीय राजनीति को एक नया आयाम दिया तथा इनके दूरदर्शी नेतृत्व ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों एवं विश्व राजनीति को नई दिशा दिखाई।

लोग अटलजी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। लोगों के इस स्वप्न के रास्ते में जो भी रूकावटें आईं इस देश की प्रचंड होती जनशक्ति के समक्ष धूल-धूसरित हो गईं। जब अटल जी प्रधानमंत्री बने देश अनेक समस्याओं से घिरा हुआ था। अर्थव्यवस्था चौपट हो रही थी। वे 'सुशासन' के अग्रदूत थे और 'विकास पुरुष' के रूप में जाने गये। यह पहली बार था जब विकास की राजनीति शुरू हुई, लोगों को सरकार के विकास कार्यों से जोड़ा गया। स्वर्णिम चतुर्भुज, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, सर्व शिक्षा अभियान, सागरमाला परियोजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, अंत्योदय अन्न योजना और इस तरह की अनेक अभिनव पहल ने इस देश में सुशासन और विकास की राजनीति का सूत्रपात किया।

अटल जी का नेतृत्व और उनके भाषणों ने दशकों तक राष्ट्र को मंत्रमुग्ध रखा। पहली बार उनकी छाप संसद पर पड़ी जब वे 1957 में लोकसभा के लिए चुने गये। वे हमेशा सार्वजनिक जीवन में सिद्धांत एवं नैतिकता के पक्षधर रहे। उनके भाषण देश के लिए प्रेरणादाक हैं। राजनीति को सत्ता-केन्द्रित अवसरवाद से विमुख कर सेवाभावी अवसर पैदा करने का मंच बनाने में वे सफल रहे। उनके 90वें जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाने से सुशासन एवं विकास का संदेश दूर-दूर तक पहुंचेगा। यह समय है कि हम पुनः अपने आप को सुशासन के प्रति समर्पित करें। यह अटल जी की ही प्रेरणा थी कि भाजपा शासित राज्यों ने सुशासन में नए इतिहास रचे हैं। आज अटल जी सार्वजनिक जीवन में नहीं हैं एवं अस्वस्थ हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अच्छा स्वास्थ्य एवं शक्ति प्रदान करें।■

'विजय दिवस रैली, कोलकाता

राज्य में भाजपा का विस्तार तृणमूल के लिए अभिशाप बना

पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास चल रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने बिना बात किसी आधार पर भाजपा को कोलकाता में सभा करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया था। लोकतंत्र में यह बात सुनने में नहीं आती है कि जहां किसी विपक्षी पार्टी को राज्य में रैली या सार्वजनिक सभा करने के लिए अदालत की शरण में जाना पड़े। स्पष्ट है कि भाजपा को अनुमति न देने का फैसला सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कहने पर किया गया। परन्तु न्याय और लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए न्यायालय ने भाजपा को रैली करने की अनुमति प्रदान की जबकि म्युनिसिपिल कार्पोरेशन, पुलिस और अग्नि-विभाग ने सभास्थल का निरीक्षण करने के बाद अनुमति देने से इंकार कर दिया था। न्यायालय ने कहा कि भाजपा रैली कर सकती है। सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस राज्य में भाजपा को विस्तार करने से रोकने लिए हरसंभव काशिश कर रही है, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय ने उसके इरादों पर पानी फेर दिया। ममता बैनर्जी पश्चिम बंगाल में मोदी लहर रोकने के लिए हर तरह की चाल चलने का प्रयास कर रही है। भाजपा द्वारा लोकसभा की एक सीट जीतने और एक सीट विधानसभा की जीतने से पश्चिम बंगाल के सभी समीकरण बदल गए हैं। यह केवल एक सीट की विजय नहीं, बल्कि जनता का भारी पैमाने पर भाजपा की तरफ झुकाव और बड़ी संख्या में लोगों का भाजपा में शामिल होना ममता बैनर्जी में घबराहट पैदा कर रहा है जिससे मुख्यमंत्री भाजपा को हटाने के लिए वामपंथी दलों और कांग्रेस तक से सम्पर्क कर बात कर रही है। और यदि भाजपा अध्यक्ष श्री अमित शाह की रैली कोई संकेत दे रही है तो ममता दीदी के दिन गिने चुने रह गए हैं। लोगों ने तृणमूल को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है जो अब भ्रष्टाचार, घोटाले, पतनोन्मुख नीतियों, अव्यवस्था, महिलाओं पर अत्याचार और कुशासन का पर्याय बन कर रह गई है।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के कोलकाता रैली में भाषण के मुख्य अंश नीचे प्रकाशित किए जा रहे हैं:

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कोलकाता के विक्टोरिया हाउस पर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। 'विजय दिवस' व 'उत्थान दिवस' के रूप में आयोजित हुई इस जन सभा में लाखों की तादाद में लोग उपस्थित हुए। श्री शाह ने इस अवसर पर पश्चिम बंगाल की जनता से तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकने और राज्य में अगली सरकार भाजपा के नेतृत्व में बनाने का आह्वान किया।

श्री शाह ने कहा, ''दीदी (ममता बनर्जी) यहां सभा की अनुमति नहीं देना चाहती थीं। दीदी ने मंच छोटा करवा दिया ताकि कम लोग बैठ पाएं। दीदी आप मंच तो छोटा कर सकती हो मगर बंगाल के लोगों के दिल में बीजेपी ने जो जगह बनाई है उससे बीजेपी को आप निकाल नहीं सकतीं। यह रैली दिखा रही है कि तृणमूल सरकार की उलटी गिनती शुरु हो गई है। 30 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल ईकाई छह साल से बीजेपी उत्थान दिवस मना रही है। लेकिन अगले 30 नवंबर को बीजेपी उत्थान दिवस नहीं बल्कि तृणमूल का पतन दिवस होगा। यह निश्चित दिखाई दे रहा है। जो सरकार जन भावनाओं और जन सैलाब को रोकना चाहती है, वह चाहे किसी की भी सरकार हो लंबी नहीं चलती। वह सरकार हमेशा गिरती है।''

श्री शाह ने कहा कि पश्चिम

बंगाल आज ऐतिहासिक मोड़ पर है। 27 साल के कम्युनिस्ट शासन को हटाने के बाद बड़ी आशा से लोगों ने तृणमूल कांग्रेस को चुना था। इस दृष्टि से चुना था कि बंगाल का विकास होगा, गांव में रोजगार मिलेगा, पीने का पानी पहुंचेगा, विकास के कार्य होंगे लेकिन साढ़े तीन साल बाद बंगाल वहीं का वहीं रह गया और कुछ ज्यादा पिछड़ गया।

श्री शाह ने कहा, ''तृणमूल के सांसद संसद के अंदर काली शॉल ओढ़कर और काला छाता लेकर जाते हैं। वे ब्लैककमनी के विरोध में प्रदर्शन करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं ममता जी आप सांसदों को तो कालेधन के विरोध में भेज रही हैं लेकिन शारदा चिटफंड में जो पैसा गया है वह ब्लैक है या व्हाइट है उसके दोषियों को आप क्यों बचा रही हैं।''

श्री शाह ने कहा कि ममता बनर्जी ने सिंगूर का आन्दोलन किया था। वहां सिर्फ 1200 लोगों की जमीन गई थी। ममता ने आमरण अनशन किया था। आज शारदा चिटफंड और बाकी चिटफंड में 17 लाख से ज्यादा लोगों के पैसे फंसे, ममता दीदी रोड पर आन्दोलन करने क्यों नहीं आतीं। जिन लोगों के पैसे फंसे हैं उनके लिए आपकी कोई जिम्मेदारी है या नहीं। जिन लोगों के पैसे फंसे हैं उनके लिए आपके मन में चिंता है या नहीं। चिटफंड के साथ आखिर कौन लोग जुड़े हैं। पहले तो आरोप लगता था लेकिन अब सिद्ध हो गया है कि टीएमसी के नेता ही इस चिटफंड को चलाने में मदद करते थे।

श्री शाह ने कहा कि ममता आरोप लगा रही हैं कि सीबीआई उनकी पार्टी के नेताओं को फंसा रही है। वह ममता को चुनौती देते हैं कि सीबीआई फंसा रही है या नहीं, यह तो अदालत तय कर देगी। ममताजी अगर आप में हिम्मत है तो कह दीजिए कि जिन लोगों को सीबीआई ने पकड़ा है वे निर्दोष हैं। जिन लोगों ने लाखों लोगों के पैसे का गबन किया है, ममता दीदी उन्हें बचाना चाहती हैं। सृजोय घोष कौन हैं, कुणाल बाबू कौन हैं, ममता जी की पेंटिंग को किसने खरीदा था। ममताजी आप बताइये कि श्यामल सेन कमीशन को आपने क्यों बंद कर दिया। आप बताइये कि टीएमसी के नेताओं को शारदा चिटफंड से फायदा हुआ है या नहीं । अगर हुआ है तो आप कैसे कह सकती हैं कि सीबीआई निर्दोष लोगों को फंसा रही हैं। यही ममता बनर्जी जो आमरण अनशन पर बैठी थीं, आज चिटफंड के आरोपियों को बचाने के लिए आगे आ रही है। यह परिवर्तन बंगाल की जनता अच्छी तरह से जानती है।

श्री शाह ने कहा कि ममता बनर्जी ने चिटफंड के आरोपियों को बचाने के साथ ही देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। ममता ने बर्धमान धमाकों के आरोपियों को बचाने की कोशिश की है। दो अक्टूबर को बर्धमान में बम विस्फोट में जिस व्यक्ति की मौत हुई वह पहले भी आरोपी रहा है, उसे पश्चिम बंगाल पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा। जब एनआइए इस मामले की जांच कर रही है तो आप आज भी वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। आप किसको बचाना चाहती हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों के आधार पर आप बंगाल पर शासन नहीं कर सकतीं। बांग्लादेशी घुसपैठियों ने आपको बंगाल का मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। पश्चिम बंगाल की जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है। अगर आप बांग्लादेशी घुसपैठियों के आधार पर ही तृणमूल कांग्रेस को बचाना चाहती हैं तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ममताजी आपकी उल्टी गिनती शुरु हो गई है।

पश्चिम बंगाल आज ऐतिहासिक मोड़ पर है। 27 साल के कम्युनिस्ट शासन को हटाने के बाद बड़ी आशा से लोगों ने तृणमूल कांग्रेस को चुना था। इस दृष्टि से चुना था कि बंगाल का विकास होगा, गांव में रोजगार मिलेगा, पीने का पानी पहुंचेगा, विकास के कार्य होंगे लेकिन साढ़े तीन साल बाद बंगाल वहीं का वहीं रह गया और कुछ ज्यादा पिछड़ गया।

श्री शाह ने कहा कि बर्धमान में आरडीएक्स पकड़ा गया। एनआइए इसकी जांच कर रही है। एनआइए को रोकने के लिए संघीय ढांचे का सवाल पैदा किया जा रहा है। एनआइए को काम नहीं करने दिया जा रहा है। टीएमसी के इतने नेता इस विस्फोट के साथ जुड़े हैं। आने वाले चुनाव में ममताजी को इसका जवाब देना होगा। बर्धमान के पीछे जो लोग लगे हैं उनको पैसे किसने दिए। तब इसकी जांच शुरु हुई तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि शारदा चिटफंड के पैसे बम ब्लास्ट के लिए उपयोग हुए। ये दोनों जांच एक मोड़ पर जाकर मिल रही हैं। सीबीआई इस मामले की भी जांच कर रही है।

श्री शाह ने कहा कि ममता जी वोट बैंक की राजनति जरूर कीजिए मगर वोट बैंक की राजनीति के कारण देश की सुरक्षा को ताक पर मत रखिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण देना आप बंद कर दीजिए। देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना है तो बांग्लादेशी

घुसपैठियों को शरण मत दीजिए। जो यहां पर ब्लास्ट करने वाले हैं, उन्हें बांग्लादेश की जनता भी स्वीकार नहीं करती। ममताजी आप इन्हें क्यों बचाना चाहती हैं।

श्री शाह ने कहा कि आने वाले समय में बंगाल में बहुत से राजनीतिक बदलाव होने वाले हैं। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के मतदाताओं से अपील की कि वे बंगाल को भी विकास यात्रा के साथ जोड़ दें। आम चुनाव में जीत के बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव हुए वहां भाजपा जीती। अब झारखंड और जम्मू-कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, वहां भाजपा जीतेगी। दिल्ली और बिहार भी भाजपा जीतकर दिखाएगी। लेकिन भाजपा सच्ची जीत तभी पा सकती है जब पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बने और भाजपा का मुख्यमंत्री बने। मोदीजी का नारा- 'कांग्रेस मुक्त भारत' करने का है, मोदीजी का नारा 'तृणमूल कांग्रेस मुक्त पश्चिम बंगाल' बनाने का भी है, इसे आप लोगों को सफल बनाना होगा।

देश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में विकास की विसंगतियों को उजागकर करते हुए श्री शाह ने कहा कि पूर्व में विकास तभी होगा, जब पश्चिम बंगाल विकसित हो। पश्चिम बंगाल का विकास हो, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा मिले, दुनिया के उद्योग रोजगार लगाएं। बंगाल के किसान को सिंचाई का पानी मिले। बंगाल के युवा को रोजगार मिले तभी पूर्वी क्षेत्र विकसित हो सकता है।

श्री शाह ने कहा कि बंगाल की जनता ने कम्युनिस्ट और टीएमसी को मौका दिया लेकिन विकास नहीं हुआ। आज मोदीजी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। तृणमूल कांग्रेस के शासन में बंगाल पिछड़ रहा है। अगर मोदीजी के साथ पश्चिम बंगाल का विकास करना है तो यहां तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से उखाड़कर भाजपा का मुख्यमंत्री बनाना होगा। अगर एक बार पश्चिम बंगाल की जनता निर्णय कर ले कि मोदीजी के साथ जुड़ना है। मैं कहता हूं कि पांच साल में भाजपा पश्चिम बंगाल को पश्चिम के प्रदेशों की तरह संपन्न बनाकर देश का नंबर वन राज्य बना देगी।

आज मोदीजी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। तृणमूल कांग्रेस के शासन में बंगाल पिछड़ रहा है। अगर मोदीजी के साथ पश्चिम बंगाल का विकास करना है तो यहां तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से उखाड़कर भाजपा का मुख्यमंत्री बनाना होगा। अगर एक बार पश्चिम बंगाल की जनता निर्णय कर ले कि मोदीजी के साथ जुड़ना है। मैं कहता हूं कि पांच साल में भाजपा पश्चिम बंगाल को पश्चिम के प्रदेशों की तरह संपन्न बनाकर देश का नंबर वन राज्य बना देगी।

मोदी सरकार की छह माह की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि मोदीजी के नेतृत्व में बारंबार पेट्रोल के दाम कम हुए हैं। साथ ही महंगाई भी कम हुई है। तृणमूल कांग्रेस यूपीए की जिस सरकार का समर्थन करती थी क्या उसके शासन में कभी पेट्रोल के दाम कम हुए थे?

प्रधानमंत्री जन धन योजना का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि ममता बनर्जी सरकार इस योजना को लागू करने में केंद्र का सहयोग नहीं कर रही जिसके चलते करोड़ों लोगों के बैंक खाते नहीं खुल रहे हैं। ममता बनर्जी केंद्र की योजनाओं में रोड़े अटका रही हैं, बंगाल का विकास होने से रोक रहीं हैं।

श्री शाह ने अगले साल मई में होने वाले कोलकाता नगर निगम के चुनाव में भारी बहुमत से भाजपा को जिताने का आग्रह भी कोलकातावासियों से किया। उन्होंने कोलकाता नगर निगम के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल को अगर विकास की दौड़ में सबसे आगे ले जाना है तो शुरुआत कोलकाता से करनी होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की असली विजय तभी होगी जब पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत होगी।

श्री शाह ने कहा कि कोई भी पार्टी अब इमोशनल ब्लेकमेल करके, सादगी का नाटक करके, वोट बैंक की राजनीति करके, बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह देकर बंगाल की जनता को मूर्ख नहीं बना सकती। पश्चिम बंगाल की जनता को सुशासन और विकास चाहिए। इसलिए पश्चिम बंगाल में ऐसी सरकार चाहिए जो राष्ट्रभक्त हो, जो बर्धमान के गुनहगारों को बचाए नहीं फांसी के तख्ते पर चढ़ा दे। एक ऐसी सरकार चाहिए जो भ्रष्टाचार को रोके, जो शारदा चिटफंड के लोगों को बचाए नहीं उन्हें सलाखों के पीछे डाल दे।

इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के प्रभारी भाजपा के राष्ट्रीय सचिव श्री सिद्धार्थनाथ सिंह, भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री एस एस अहलूवालिया, श्री चंदन मित्रा और पश्चिम बंगाल की इकाई के कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। श्री शाह की मौजूदगी में रैली में आए समर्थकों ने भारी संख्या में मोबाइल के माध्यम से भाजपा की सदस्यता ली। ■

भाजपा के नेतृत्व में राजग सरकार के छह महीने

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने असाधारण उपलब्धियां अर्जित की : अमित शाह

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा नीत राजग सरकार के 26 नवम्बर 2014 को सत्ता सम्भाले छह महीने हो गये। अनेक असाधारण उपलब्धियों के अलावा सरकार ने देश को नई आशाएं और दृष्टि दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी विभिन्न देशों में गए, जिसमें उन्होंने एक आत्मविश्वास से भरपूर, सक्षम और उभरते भारत की नई छवि प्रदान की है। हर क्षेत्र से अच्छी खबरें आ रही हैं और कहा जा सकता है कि 'अच्छे दिन' की शुरूआत हो रही है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 27 नवम्बर 2014 को भाजपा के नेतृत्व में राजग सरकार की छह महीनों की उपलब्धियों पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया। हम अपने सुधी पाठकों के लिए उसे प्रकाशित कर रहे हैं :-

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार ने 26 नवंबर 2014 को छह महीने पूरे किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लोक सभा चुनाव से पहले जनता से जो वादे किए उन्हें पूरा करने को सरकार ने कई कदम उठाए हैं। छह महीने की अल्पावधि में ही राजग सरकार ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। सरकार के उपायों से न सिर्फ आम लोगों का जीवन आसान हुआ है बल्कि एक मजबूत भारत की आधारशिला रखी है। बीते छह महीने में सरकार की प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:-

महंगाई पर लगाम लगाई

सरकार ने महंगाई पर अंकुश लगाने के लिये राजकोषीय और प्रशासनिक उपाय करते हुए 500 करोड़ रुपये का मूल्य स्थिरीकरण कोष (Price Stabilization Fund) स्थापित किया। प्याज और आलू की आपूर्ति बढ़ाने को न्यूनतम निर्यात मूल्य बढ़ाया राज्यों को जमाखोरी और कालाबाजारी के मामलों को शीघ्र निपटाने को विशेष अदालतें बनाने को कहा। परिणामस्वरूप छह महीने के भीतर ही महंगाई में रिकार्ड गिरावट दर्ज हुई है। थोक महंगाई दर पांच साल के न्यूनतम स्तर पर है। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति अक्टूबर 2014 में घटकर मात्र 1.77 प्रतिशत रह गई है जबकि संप्रग शासन में अक्टूबर 2013 में यह 7.24 प्रतिशत और मई 2014 में 6.18 प्रतिशत थी। इसी तरह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति अक्टूबर 2014 में घटकर मात्र 5.52 प्रतिशत रह गई है जबकि कांग्रेस की संप्रग सरकार के शासन में अक्टूबर 2013 में यह 10.17 प्रतिशत और मई 2014 में 8.28 प्रतिशत थी। इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल भी सस्ते हुए। एक जून 2014 को नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 71.45 रुपये थी जो राजग सरकार के सत्ता में आने के बाद हुई कटौती के कारण एक नवंबर 2014 को 64.27 रुपये प्रति लीटर रह गई है। पेट्रोल की कीमत में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दर से कमी आई है। एक जून 2014 को नई दिल्ली में डीजल की कीमत प्रति लीटर 57.28 रुपये थी जो राजग सरकार बनने के बाद हुई कटौती से एक नवंबर 2014 को 53.35 रुपये प्रति लीटर रह गई है। डीजल की कीमत में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दर से कमी आई है।

रोजगार सृजन और उद्यमिता को उच्च प्राथमिकता

युवाओं के कौशल विकास के लिए अलग मंत्रालय बनाया। विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने को मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरु किया। परिणामस्वरूप मोदी सरकार के पहले छह महीने में उठाए गए कदमों से आगामी वर्षों में करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा।

भ्रष्टाचार खत्म करने पर जोर

सूचना प्रौद्योगिकी आधारित पारदर्शी तंत्र बनाकर भ्रष्टाचार

खत्म करने की दिशा में ई-क्रांति परियोजना की शुरुआत जिस पर अगले कुछ वर्षों में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे।

ई-क्रांति को अमल में लाने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरु।

विदेश में कालाधन वापस लाने को विशेष कार्यदल का गठित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 27 मई को कैबिनेट की पहली बैठक में ही विशेष जांच दल (Special Investigation Team) का गठन किया गया। इसके बाद वित्त मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय दल स्विटजरलैंड भेजा। विदेशी बैंकों में खाताधारक 427 लोगों की पहचान, 250 लोगों ने खाता होने की बात स्वीकार की ।

नीतिगत पंगुता (Policy Paralysis) को दूर किया

संप्रग कार्यकाल में बने मंत्रिसमूहों को खत्म किया। सचिवों के साथ प्रधानमंत्री ने सीधे संवाद स्थापित कर नौकरशाही को निर्णय लेने को प्रोत्साहित किया। परिणामस्वरूप केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में बेहतर समन्वय और निर्णय प्रक्रिया में तेजी।

टीम इंडिया के रूप में कार्य किया

राज्यों को साथ लेकर चलने के विचार को व्यवहार में उतारा। जम्मू कश्मीर में भीषण बाढ़ तथा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में चक्रवातीय तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं में केंद्र सरकार ने राज्यो के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया। विभिन्न कार्यक्रमों को शुरु करने से पहले राज्यों से संवाद की परंपरा शुरु की। परिणामस्वरूप प्राकृतिक आपदा से प्रभावितों को समय पर राहत और बचाव मुहैया कराना संभव हुआ।

100 नए स्मार्ट शहर बसाने की प्रक्रिया शुरू

100 नये स्मार्ट शहरों के लिये आम बजट में 7060 करोड़ रुपये का आवंटन किया। परिणामस्वरूप विकसित किए जाने वाले 100 शहरों की पहचान की गई। कई शहरों में काम शुरू ।

2019 तक स्वच्छ भारत

सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान लांच किया, स्वच्छ भारत कोष की स्थापना की। परिणामस्वरूप स्वच्छता एक आन्दोलन बन गया है, अलग-अलग क्षेत्र के लोग इससे जुड़े हैं।

उच्च अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यागयिक आयोग का गठन किया

सरकार ने राष्ट्रीय न्याययिक नियुक्ति आयोग विधेयक 2014 संसद से पारित कराया। इससे न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी आएगी।

गांवों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर काम शुरू

सरकार ने प्रधानमंत्री सांसद आदर्श गांव योजना शुरू की और योजना के तहत संसद सदस्यों ने गांवों का चयन किया, साथ ही 'रूरबन' योजना पर भी काम चल रहा है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याणकारी उपाय किए

सरकार ने जीवन प्रमाण योजना शुरु की, बचत योजनाओं में पड़ी दावारहित धनराशि का इस्तेमाल वरिष्ठतम नागरिकों को वित्तीय मदद देने के लिए करने की घोषणा की और परिणामस्वरूप पेंशनभोगियों को अब हर साल नवंबर जीवित होने का सबूत देने के लिए सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी। वित्तीय मदद मिलने से उनका जीवन आसान होगा।

आर्थिक पुनरुत्थान, विकास दर बढ़ी

लंबित आर्थिक सुधारों को लागू करते हुए कई राजकोषीय कदम उठाए जिससे निवेश चक्र को पुन: चालू किया जा सके। रेल, रक्षा और निर्माण क्षेत्र में एफडीआई नियम उदार बनाए। परिणामस्वरूप सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप विकास दर बढ़ी। वित्त वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर बढ़कर 5.7 प्रतिशत हो गयी है जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार के कार्यकाल में वित्त वर्ष 2013-14 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में यह 4.7 प्रतिशत और अंतिम तिमाही (जनवरी-मार्च) में 4.6 प्रतिशत थी। इसके साथ ही औद्योगिक उत्पादन सूचकांक ने भी रफ्तार पकड़ी। लगातार नकारात्मक वृद्धि दर्ज करने वाले औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में भी राजग सरकार की कोशिशों से अब वृद्धि होने लगी है। सितंबर 2014 में औद्योगिक उत्पोदन सूचकांक में 2.5 प्रतिशत वृद्धि हुई।

मध्यम वर्ग व नव मध्यम वर्ग की आकांक्षाएं पूरी करने पर जोर

सरकार ने आयकर से छूट की सीमा दो लाख रुपये से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए ढाई लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये की। परिणामस्वरूप महंगाई घटने तथा आयकर में राहत मिलने से मध्यम वर्ग और निम्न-मध्यम वर्ग अब अपने भविष्य के लिए निवेश कर सकता है।

कृषि को फायदेमंद बनाने के उपाय किए

सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मोबाइल मृदा

परीक्षण प्रयोगशालाएं, एमएसपी बढ़ाया। जिससे डीजल के दाम घटने से कृषि लागत कम आएगी। सरकार ने जो उपाय किए हैं उनके दूरगामी फायदे होंगे।

अविरल और निर्मल गंगा के लिए भाजपा प्रतिबद्ध

सरकार ने गंगा के लिए अलग मंत्रालय बनाया, आम बजट में 2037 करोड़ रुपये की नमामि गंगे योजना घोषित की। परिणामस्वरूप गंगा को प्रदूषण मुक्त करने का कार्यक्रम शुरु, प्रदूषणकारी उद्योगों को मार्च 2015 तक सेंसर लगाने को कहा। गंगा में गंदगी गिरने पर पूर्णत: रोक सुनिश्चित होगी।

गाय व गौवंश का संरक्षण

सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया और देशी गायों के संरक्षण के लिए 500 करोड़ रुपये की इस योजना के तहत कई कार्यक्रमों को मंजूरी दी गई।

कुछ अन्य ऐतिहासिक उपलब्धियां

प्रधानमंत्री जन धन योजना में खुले गरीबों के बैंक खाते प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त 2014 को लालकिले की प्राचीर से इस योजना की घोषणा की और 28 अगस्त 2014 को इसे राष्ट्रीय स्तर पर लांच कर दिया। 22 नवंबर 2014 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 7.73 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इसमें से 4.58 करोड़ बैंक खाते ग्रामीण क्षेत्र में तथा 3.14 करोड़ बैंक खाते शहरी क्षेत्र में हैं। जनगणना 2011 के अनुसार देश में 40 प्रतिशत परिवारों के पास बैंक खाते नहीं थे।

'मेक इन इंडिया' की शुरुआत:

प्रधानमंत्री ने 25 सितंबर 2014 को 'मेक इन इंडिया' अभियान लांच किया। इसे सफल बनाने के लिए रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर अधिक किया गया है। इसके अलावा कई अन्य क्षेत्रों में भी एफडीआई की राह आसान बनाई। इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मिलने का रास्ता तैयार होगा।

कूटनीतिक मोर्चे पर लहराया परचम:

विदेश नीति के मोर्चे पर भी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने परचम लहराया है। सीमा पर गोलीबारी के मुद्दे पर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया है। अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत से दुनियाभर में भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा हुआ है। इराक संकट के दौरान फंसे भारतीयों को सफलतापूर्वक सुरक्षित निकाला गया। पड़ोसी देशों के साथ सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रखने के लिए सार्क देशों के प्रमुखों को शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया।

डब्ल्यूटीओ में किसानों और गरीबों के हितों की रक्षा: भारत ने जुलाई 2014 में डब्ल्यूटीओ के व्यापार सरलीकरण समझौते पर दस्तखत करने से इंकार कर दिया। भारत ने साफ कहा कि पहले खाद्य सुरक्षा और कृषि सब्सिडी के मुद्दे पर उसकी चिंताएं दूर होनी चाहिए। राजग सरकार के इस सख्त रुख की वजह से ही अमेरिका, भारत के नजरिये का समर्थन करने को मजबूर हुआ। डब्ल्यूटीओ वार्ताओं में भारत की यह बड़ी जीत है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम: कर्मचारियों और श्रमिकों की भलाई के लिए सरकार ने यह कार्यक्रम अक्टूबर 2014 में लांच किया। इसके साथ ही न्यूनतम पेंशन भी 1000 रुपये तय की। साथ ही पीएफ के लिए यूनिवर्सल नंबर का शुभारंभ जिसकी मदद से कर्मचारी अपने पीएफ खाते को कहीं से भी संचालित कर सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास पड़े दावारहित 27,000 करोड़ रुपयों को श्रमिकों के हितों के लिए खर्च किया जाएगा।

सरकारी कार्यशैली में व्यापक बदलाव: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकारी कार्यशैली में व्यापक परिवर्तन आया है। सरकारी निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज हुई है। संप्रग सरकार के कार्यकाल में सरकार में नीतिगत फैसले लेने की प्रक्रिया बिल्कुल ठप पड़ गई थी। इस संबंध में सबसे अहम फैसला संप्रग शासन में बने मंत्रि-समूहों को खत्म करके लिया गया है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों की हाजिरी के लिए http://attendance.gov.in/ शुरू की ताकि केंद्र के सभी कर्मचारी समय पर दफ्तर पहुंचें।

रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाई, रक्षा खरीद प्रक्रिया को गति दी: लंबित आर्थिक सुधारों को लागू करते हुए सरकार ने रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत की। फिलहाल भारत 70 प्रतिशत रक्षा सामान आयात करता है। इस फैसले से देश में ही रक्षा उपकरणों की मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सकेगा। सरकार ने एक फैसले में ही 80,000 करोड़ रुपये की रक्षा खरीद को मंजूरी दी। यूपीए सरकार ने रक्षा खरीद पर कोई फैसला न करके देश की सुरक्षा से समझौता किया था। रक्षा क्षेत्र के साथ-साथ रेल और निर्माण क्षेत्र में भी एफडीआई की सीमा बढ़ाई गई।

24 घंटे बिजली: चौबीस घंटे बिजली देने का वादा पूरा करने के लिए मोदी सरकार ने 43,000 करोड़ रुपये की

शेष पृष्ठ 30 पर

सार्क शिखर सम्मेलन : काठमांडू (नेपाल)

साथ होने से बढ़ेगी ताकत : नरेन्द्र मोदी

'शांति और समृद्धि के लिए मजबूत क्षेत्रीय समीकरण' विषय पर आयोजित 18वीं सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 26 एवं 27 नवंबर को काठमांडू (नेपाल) में रहे। गत चार मास के दौरान यह प्रधानमंत्री की दूसरी नेपाल यात्रा थी। इस सम्मेलन में बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों ने हिस्सा लिया और सार्क के 9 पर्यवेक्षक ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार और अमेरिका भी उपस्थित थे। अपनी नेपाल यात्रा से पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह मेरी पहली सार्क शिखर सम्मेलन है। छह महीने पहले शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के नेताओं ने समारोह में उपस्थित होकर शुभ शुरुआत के साथ बड़े पैमाने पर बातचीत भी की थी। अपने पड़ोसियों के साथ घनिष्ठ संबंधों का विकास मेरी सरकार के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता है। श्री मोदी ने कहा कि भारत हमेशा से ही दक्षिण एशियाई क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सभी स्तरों पर अधिक से अधिक क्षेत्रीय एकीकरण के महत्व पर जोर देता आ रहा है।

भारत-नेपाल द्विपक्षीय वार्ता में कई समझौतों पर हस्ताक्षर

18वें सार्क सम्मेलन में भाग लेने के लिए काठमांडू पहुंचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का हवाई अड्डे से लेकर होटल तक जोर-दार स्वागत किया गया। यहां पर उन्होंने नेपाल के साथ कुछ एमओयू को भी साइन किया और नई घोषणाएं भी की। यहां पहुंचने पर उन्होंने कहा कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि बहुत ही कम समय में एक बार फिर मेरा नेपाल की भूमि पर आना हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि अगर नेपाल खुश नहीं है तो भारत मुस्कुरा नहीं सकता है और नेपाल के खुश रहने पर भारत आनंदित होता है।

जोरदार हुआ स्वागत

नेपाल पहुंचने पर हवाई अड्डे पर श्री मोदी को को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यहां पर नेपाल के उप-प्रधानमंत्री श्री बाम देव गौतम ने उनकी अगुआई की। यहां से होटल पहुंचने पर उनका परंपरागत तरीके से शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया गया।

काठमांडू-दिल्ली बस सेवा की शुरुआत

प्रधानमंत्री ने काठमांडू-दिल्ली बस

सेवा का झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

ट्रामा सेंटर का किया उद्घाटन

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने काठमांडू में ट्रामा सेंटर का भी उद्घाटन किया। यह ट्रामा सेंटर भारत के सहयोग से बना है। यह 200 बेड का अस्पताल है, जिसमें सभी अत्याधुनिक तकनीक मौजूद हैं। अपने उदघाटन भाषण में उन्होंने कहा कि भारत हमेशा दूसरों की मदद करता रहा है। हमारे लिए यह बहुत गर्व की बात है कि हम अपनों की जिंदगियां बचाने में भी मदद कर पाएंगे।

ध्रुव और चलती-फिरती लैब की भेंट

यहां पहुंचने के बाद उन्होंने नेपाल को ध्रुव हैलिकॉप्टर भेंट किया। इसके अलावा उन्होंने मिट्टी की जांच के लिए भी एक चलती-फिरती लैब नेपाल को मुहैया करवाई।

नेपाल में संविधान गठन का किया समर्थन

नेपाल में नए संविधान के गठन को लेकर भी श्री मोदी ने यहां पर अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने कहा कि भारत-नेपाल का अटूट नाता है।

मैं एक मित्र राष्ट्र के नाते प्रार्थना करता हूं आप सहमति से संविधान बनाइए, जल्दी से संविधान बनाइए। मेरा आग्रह है कि नेपाल का संविधान ऐसा बने जिसमें हर नेपाली वर्ग का प्रतिनिधित्व हो, संविधान संख्या बल से नहीं सहमति से बने।

सिंह दरबार में की नेपाल के प्रधानमंत्री से मुलाकात

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री श्री सुशील कोइराला से भी सिंह दरबार में मुलाकात की और कुछ एमओयू को भी साइन किया। एक समझौते के मुताबिक अब भारत से आए पयर्टकों को अपने साथ 25 हजार रुपये लाने की इजाजत होगी। इसमें केवल पांच सौ और हजार के नोट ही स्वीकार किए जाएंगे। ■

सार्क बैठक में प्रधानमंत्री का संबोधन

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में सबसे पहले सार्क सम्मेलन के शानदार आयोजन के लिए नेपाल का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि काठमांडू आकर खुश हूं। मै पहली बार सार्क सम्मेलन में हिस्सा ले रहा हूं। इसमें मैं एकता का नया उदय देख रहा हूं। अच्छा पड़ोसी मिले यह सभी की इच्छा होती है। इस काम में सार्क महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। प्रधानमंत्री ने सार्क नेताओं से कहा कि मैंने पूरे विश्व की शुभकामनाओं के साथ कार्यभार संभाला, लेकिन मुझे जिसने प्रेरित किया, वह आपकी निजी मौजूदगी थी।

आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह क्षेत्र की सबसे बड़ी और विकट समस्या है। उन्होंने कहा कि आज 26/11मुंबई हमले की बरसी है। इस आतंकी हमले का दर्द कभी खत्म होने वाला नहीं है। 26/11 के आतंकी हमले में मारे गए लोगों का दर्द आज भी ताजा है। उन्होंने कहा कि हमें एक दूसरे के नागरिकों की परवाह करनी होगी। हम एक दूसरे के नागरिकों की चिंता करेंगे तो दोस्ती बढ़ेगी। श्री मोदी ने कहा कि पास होने से, साथ होने से ज्यादा ताकत मिलती है। श्री मोदी ने कहा, पिछले कुछ महीनों में मैं दुनिया भर में घूमा हूं और लगभग सभी देशों की समस्याएं एक जैसी हैं। हम लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती विकास के पहाड़ पर चढ़ने की है। सार्क देशों में जाना महंगा है, सिंगापुर और बैंकॉक जाना सस्ता है।

श्री मोदी ने कहा कि सार्क देशों के करीब आने की गति धीमी है। श्री मोदी ने कहा, जब भी हम सार्क देशों का जिक्र करते हैं, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमें दो ही प्रतिक्रियाएं सुनने को मिलती हैं, निराशावाद और संशयवाद।

प्रधानमंत्री ने कहा, मैं जानता हूं कि भारत को ही नेतृत्व करना होगा, और हम अपनी भूमिका जरूर निभाएंगे। बुनियादी ढांचे का विकास भारत में मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। श्री मोदी ने कहा, हम (दक्षिण एशियाई देश) सभी पास-पास जरूर हैं, लेकिन साथ-साथ नहीं हैं, जबकि हमें समझना चाहिए कि साथ आ जाने से हम सबकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी।

श्री मोदी ने कहा कि सार्क देशों से बीमारी के इलाज के लिए भारत आने वालों के लिए मरीज और उसके एक सहायक को तत्काल मेडिकल वीजा उपलब्ध कराया जाएगा। श्री मोदी ने सार्क देशों के बीच व्यापार बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिले। हमारे सामने एक जैसी चुनौतियां हैं। क्षेत्र के विकास का स्पीड काफी स्लो है।

श्री मोदी ने कहा कि सार्क में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की जरूरत है। सार्क देशों का विकास होना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक दूसरे देश के बीच रेल और सड़क संपर्क होना जरूरी है। सार्क देशों को बिजली का उत्पादन बढ़ाना होगा। क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ाना होगा। ■

पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र एक 'प्राकृतिक आर्थिक क्षेत्र' है : नरेन्द्र मोदी

भारतीय जनता पार्टी ने देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र को सदा महत्व दिया है और शेष भारत के साथ इसके विकास और जोड़ने के लिए प्रत्येक प्रयास का समर्थन भी किया है। पार्टी ने इस क्षेत्र की शांति और समृद्धि के लिए कार्य किया है। जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केन्द्र में सरकार का गठन हुआ तो पहली बार इस क्षेत्र के के लिए एक अलग मंत्रालय और विभिन्न परिषदों के गठन के साथ अलग से बजट प्रावधान बनाए गए तथा निर्देश दिया कि प्रत्येक विभाग को पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अपने बजट का दस प्रतिशत अंशदान करना होगा और इस क्षेत्र का बजट अव्यपगत रहेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चुनाव अभियान के दौरान वाजपेयी की पूर्वोत्तर की नीति को जारी रखने का वायदा किया था और अब वह दिशा में अपना वायदा पूरा कर रहे हैं। श्री नरेन्द्र मोदी ने हाल जी में असम, मणिपुर, नगालैण्ड और त्रिपुरा की यात्रा की एवं लोगों को अपने समर्थन का पुन: विश्वास लिया तथा उन्होंने इस क्षेत्र के लिए विकास, शांति और सद्भावना की एक नई दृष्टि पेश की। हम यहां अपने सुधी पाठकों के लिए इस क्षेत्र में उनकी यात्रा की संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं :-

नगालैण्ड को विश्व आईटी व्यापार में अपना स्थान बनाना चाहिए

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 1 दिसम्बर को नगालैण्ड में कोहिमा में नगालैण्ड होर्नबिल समारोह में उपस्थित हुए। इस अवसर पर लोगों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने नगालैण्ड राज्य-निर्माण की 51वीं जयंती पर बधाई दी।

नरेन्द्र मोदी ने कहा कि नगालैण्ड दिल्ली से 10-15 घण्टे की यात्रा कर पहुंचा जाता है, परन्तु यहां कोई भी प्रधानमंत्री 10 वर्ष से नहीं आया था।

किसी प्रधानमंत्री की पिछली औपचारिक यात्रा अक्टूबर 2003 में हुई थी जब प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी कोहिमा आए थे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार नगा इतिहस की अद्भुत नवीनता को जानती है। इस लाइन ने नगाओं के विद्रोही जख्मों पर मरहम लगाया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को ''प्राकृतिक आर्थिक क्षेत्र'' अर्थात् 'एनईजेड' बताया जिसके अभी तक पूरे संसाधनों का इस्तेमाल नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि इस 'एनईजेड' को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ के लिए प्रयुक्त किया जाना चाहिए। कोहिमा में होर्नबिल समारोह के उद्घाटन पर अपने सम्बोधन में नगालैण्ड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की सराहना की और नगा लोगों में बसी कठोर परिश्रम, सादगी और ईमानदारी की प्रशंसा की। उन्होंने समारोह करने के लिए नगाओं को बधाई देते हुए राज्य की सांस्कृतिक वैविध्यता का जिक्र किया।

प्रधानमंत्री ने उनके राज्य-निर्माण दिवस पर नगालैण्ड के लोगों का अभिनन्दन किया और उनसे पिछले 50 वर्षों में जो कुछ पाया है, उस पर अंतर्मथंन करने को कहा तथा देखें कि क्या कुछ पा लिया है।

प्रधानमंत्री ने समृद्ध बायोडाइवर्सिटी और युवा अंग्रेजी भाषी जनसंख्या का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में पर्यटन सुनिश्चित हो सकेगा तथा राज्य में निवेश होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में विश्व का आईटी कारोबार पहुंचना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बॉक्सिंग, तीरंदाजी, फुटबाल और ताइक्वांडो खेल की बड़ी संभावनाएं है और इन्हें प्राप्त करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के बाद एक दशक तक किसी ने नगालैण्ड की यात्रा नहीं की। उन्होंने राज्य के लोगों को भरोसा दिलाया कि उन्हें प्रधानमंत्री की अगली यात्रा के लिए इतना लम्बा इंतजार नहीं करना होगा। उन्होंने कहा कि फिर से ये देखने के लिए आएंगे कि जो कुछ उन्होंने कहा है कि वह वास्तविकता में परिणित हो।

प्रधानमंत्री ने मेंदीपथर, मेघायल से गुवाहाटी तक पहली गाड़ी रवाना की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्वोत्तर के विकास की प्राथमिकता देने के सरकार के फैसले को रेखांकित किया है। वह मेंदीपथर, मेघायल से गुवाहाटी तक पहली रेलगाड़ी की हरी झण्डी दिखा कर रवाना करने के अवसर पर बोल रहे थे। और वे 29 नवम्बर को गुवाहाटी में भैरवी से सैरंग तक एक नई रेललाइन के लिए 'प्लेक' का अनावरण कर रहे थे। उन्होंने इस भारतीय रेलवे के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवसर बताया, जब एक राज्य को रेल नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने उनकी सरकार के पिछले छह महीनों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए ली गई पहलों का उल्लेख भी किया। उन्होंने पूर्वोत्तर के 1000 विद्यार्थियों के लिए ईशान उदय विशेष छात्रवृत्तियों का उल्लेख किया और पूर्वोत्तर के कालेजों के 2000 विद्यार्थियों और 500 फैकल्टी सदस्यों के लिए ईशान विकास योजना को प्रतिवर्ष देश के विभिन्न भागों में जाने की योजना बताया।

उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के विकास के लिए केन्द्रीय बजट में 53,000 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए नई रेलवे लाइनें बिछाने के लिए 28,000 करोड़ रूपए निर्धारित किए गए हैं। 5000 करोड़ रूपए का प्रावधान अन्तर्राष्ट्रीय पावर ट्रांसमिशन व्यवस्था के लिए रखा गया हे, तो इतनी ही धनराशि 2जी मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए रखी गई है।

मणिपुर में एक राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना होगी और इस क्षेत्र में नए छह कृषि कालेजों को स्थापित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार, यदि घर के पूर्वोत्तर कोने को ढंग से रखा जाए तो पूरा घर सुरक्षित रहता है। उन्होंने कहा कि वह इतना ही जानते हैं कि यदि भारत को समृद्ध बनाना है तो पूर्वोत्तर के विकास को प्राथमिकता देनी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाए तो लोग स्वयं ही बहुत का विकास कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने दक्षिण कोरिया का उदाहरण दिया कि किस प्रकार से वहां विकास की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के आठ राज्यों में अच्छी कनेक्टिविटी बनानी हो तो पूरा क्षेत्र समृद्ध हो जाएगा और पर्यटन फलेगा-फूलेगा। उन्होंने आगे कहा कि नई सरकार केन्द्रीय बजट में पूर्वोत्तर में नई रेल-लाइन बिछाने के लिए 28,000 करोड़ रूपए का प्रावधान दे। पूरा जगत मानता है कि यह शताब्दी एशिया की शताब्दी है। अत: इस समय आवश्यकता है कि 'एक्ट ईस्ट' की बजाय 'पूर्व को ओर देखो' नीति पर चलो और पूरे क्षेत्र को म्यांमार तथा इसके पार के देशों से जोड़ो। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को अब अगली पीढ़ी के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा करना है जिसमें

हाईवेज और आई-वेज दोनों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कोई डिजीटल विभाजन नहीं होना चाहिए और डिजीटल भारत में पूर्वोत्तर को शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गैस-ग्रिड क्यों न हो, क्यों 24 घण्टे बिजली ना मिले और उनका यह विश्वास था कि यदि अगली पीढ़ी का इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक भारत में महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि आप्टिकल फाइबर नेटवर्क से पूर्वोत्तर को अत्यंत अवसर प्राप्त होंगे।

प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा में पलटाना पॉवर प्रोजेक्ट की दूसरी इकाई का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 1 दिसम्बर को उदयपुर आईएनसी त्रिपुरा पॉवर प्रोजेक्ट की दूसरी इकाई का उद्घाटन किया और राष्ट्र को समर्पित करते हुए कहा कि चारूसून्नी रेवोल्युशन के आधार पर पूर्वोत्तर की कायापलट हो जाएगी। उद्घाटन समारोह में जनसमूह को सम्बोधित करते हुए

प्रधानमंत्री ने कहा कि रेल, सड़क, वायु और जलमार्ग से कनेक्ट कर इस क्षेत्र के विकास करने की योजना केन्द्र के मन में लम्बे समय से चल रही है।

श्री मोदी ने क्षेत्र के विकास को मन में रखते हुए दूसरी हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, भगवा क्रांति और नीली क्रांति लाने की सोची है। सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में एनडीए सरकार की सकारात्मक दृष्टि को आगे बढ़ाने वाली है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन, ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों की अपार सम्भावनाएं हैं जिनका मुकाबला कई देशों से किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के आमंत्रण पर त्रिपुरा के मुख्य मंत्री श्री माणिक सरकार से भी मिले।

प्रधानमंत्री ने इम्फाल में सांगाई समारोह में भाग लिया

नगालैण्ड में होर्नबिल समारोह में उपस्थिति से एक दिन पहले, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 30 नवम्बर को इम्फाल के मणिपुर में सांगाई समारोह में भाग लिया।

रोजगार विषय पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र कॉल सेन्टर के लिए हब रूप में उभर कर आ सकता है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री द्वारा सड़कें और हस्पताल सुधारने की बात का संदर्भ देते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार की ओर निहार रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष केन्द्र के बजट में पूर्वोत्तर में 60,000 करोड़ रूपए के बजट का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि मैं इस ओर से आए प्रत्येक अनुरोध को देखूंगा और विचार करूंगा कि क्या कुछ किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने की इच्छुक है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि म्यांमार में उनकी हाल की यात्रा में इम्फाल और दक्षिणी एशिया के बीच कनेक्टिविटी सुधार करने के लिए पर्याप्त ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि काफी पहल की गई है और आने वाले दिनो में इनका प्रभाव दिखाई पड़ने लगेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मणिपुर सांगाई समारोह के समापन समारोह में भाग लेकर वह यह संदेश देना चाहते थे कि देश के शेष भाग को राज्य में पर्यटन की सम्भावनाओं को देखना चाहिए। ■

श्रद्धांजलि

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री वीआर कृष्णा अय्यर के निधन पर शोक संदेश

गत 4 दिसम्बर को सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री वीआर कृष्णा अय्यर के निधन का समाचार सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ है। न्यायमूर्ति अय्यर को उनके स्पष्टवादी विचारों के लिए जाना जाता है। वे राष्ट्रवादी विचारधारा के संवाहक थे। उनके निधन से देश को अपूरणीय क्षति हुई है। मैं अपनी पार्टी की ओर से उनके परिवार के प्रति शोक संवेदना प्रकट करता हूं और ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। ■

संसद में बहस : लोकसभा

विदेश में कालाधन जमा करने वाले दोषियों को जल्दी ही कड़ा दण्ड मिलेगा : अरुण जेटली

संसद के वर्तमान सत्र में कालेधन के मुद्दे पर चर्चा हुई। कांग्रेस ने कभी भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों पर भी विशेष जांच टीम का गठन नहीं किया, आज वही कांग्रेस केन्द्र में राजग सरकार के नेतृत्व पर उंगली उठा रही है। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने सत्ता में आते ही काले धन पर जस्टिस एमबी शाह की अध्यक्षता में विशेष जांच दल का गठन कर दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने विदेशों में जमा कालेधन पर और भी कई कदम उठाए। प्रधान मंत्री ने जी-20 फोरम में यह मुद्दा उठाया और उन्होंने निरन्तर प्रयास करते हुए काले धन को वापस लाने का संकल्प किया। वित्तमंत्री, कार्पोरेट कार्य और सूचना तथा प्रसारण मंत्री श्री अरुण जेटली ने 27 नवम्बर 2014 को लोकसभा में काले धन के मुद्दे का जवाब दिया।

इस भाषण का संपादित पाठ हम यहां प्रकाशित कर रहे हैं :-

हम लोग जब नौजवान थे और नए-नए वकील बने तो हम लोगों को एक सुझाव दिया जाता था कि जिस मुकदमे में तथ्य मजबूत हैं, तथ्यों की बात करो, जहां कानून मजबूत है, कानून की बात करो और जहां दोनों कमजोर हों, तो फिर मेज़ पर थोड़ा सा दबाव डालते रहो। अब पूरी व्यवस्था को समझने के स्थान पर यही कहना कि सरकार ने क्या-क्या किया है, मैं इस बारे में आपको पूरे आंकड़े दूंगा।

कई माननीय सदस्यों ने, चाहे खड़गे जी ने पूछा हो या मुलायम सिंह जी ने पूछा हो कि यह स्थिति अब कहां खड़ी है, पैसा आएगा या नहीं आएगा, मुलायम सिंह जी ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों ने पैसा निकाल लिया हो। मुलायम सिंह जी, सच्चाई यही है जो आपने कहा। मैं उसके भी तथ्य आपको देता हूं। यह केवल राजनैतिक अंतर्विरोध का विषय नहीं हैं।

तीन प्रकार की स्थितियों से निकलकर हम अब एटोमैटिक एक्सचेंज ऑफ इंफार्मेशन में जाते हैं। तीन तरह के खाते हैं, जिनके सम्बन्ध में जानकारी है, या सम्भव हैं। पहले खाते हैं 28 लोगों के जौ लिचनस्टीन नाम का एक टैक्स हैवन है, जहां लोग इस प्रकार का पैसा रखते हैं, उन खातों की जानकारी जर्मनी को मिली। जर्मनी के साथ भारत का समझौता था और जर्मनी ने उसके तहत जानकारी हमें दी। हमें उसकी जांच करनी थी और सबूत इकट्ठे करने थे। उस सबूत में यह पता चला कि कुछ लोग एनआरआई हैं। अगर आप नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं तो आपको अधिकार है खाता रखने का, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। एक व्यक्ति की उसमें मृत्यु हो गई। ऐसे 18 लोग थे उनमें से जिनके नाजायज खाते थे। लेकिन जब तक यह प्रक्रिया पूरी होती, तब यूपीए सरकार थी, वे लोग अपना पैसा वहां से निकालते रहे हमने उन 18 के 18 के खिलाफ इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स कंक्लूड कर दी हैं। उस नाजायज पैसे की जो भी उन पर सजा या पैनल्टी लगा सकते थे टैक्स वगैरह, वे सारे उन पर लगा दिए हैं। उसके बाद उन 18 के 18 फौजदारी का मुकदमा भारत के अंदर डाल दिया हैं

इसके अतिरिक्त एचएसबीसी का जिनेवा का जो बैंक था, यह पूरा मल्टी इंटरनेशनल बैंक है, उस बैंक का एक कर्मचारी व्हिसल ब्लोअर बन गया और उनका सॉफ्टवेयर वहां से उठाकर ले गया। उस सॉफ्टवेयर को ले जाने के बाद उसने वह सारा का सारा फ्रांस की सरकार को दे दिया। कुछ लोग कहते हैं कि उसने वह बेच दिया। अब फ्रांस के साथ चूंकि हमारा समझौता था। दुनिया के अन्य देशों के साथ भी था। फ्रांस ने हर देश के खातों की जानकारी उन देशों को दे दी। भारत को जानकारी मिली कि 2005 और 2007 के बीच

में स्विट्जरलैंड के एचएसबीसी के बैंक में इन 627 लोगों के ये एकाउंट्स थे। ये जानकारी 2007 के बाद 2008 और 2009 या 2010 में मिली होगी। हमारा स्विट्जरलैंड से समझौता था, उसमें यह प्रावधान ही नहीं था कि स्विट्जरलैंड हमें जानकारी दे। सन् 2011 में जाकर भारत सरकार ने स्विट्जरलैंड से यह समझौता किया। उन खाते वालों को 2007 से 2011 तक की मोहलत मिल गई। इसमें वे क्या करते, खाते में कितना पैसा छोड़ते। सन् 2011 के बाद जब यूपीए ने उनसे पूछा कि हमें जानकारी दो, सबूत दो, तो उन्होंने कहा कि यह जो सारी जानकारी आपको मिली है, इसमें केवल नाम हैं, थोड़ी सी जानकारी है, सबूत नहीं हैं। हम आपको सबूत नहीं देंगे, क्योंकि यह चोरी के आधार पर मिले हैं, स्टोलन डैटा है और स्विट्जरलैंड स्टोलन डेटा में आपके साथ सहयोग नहीं करेगा। जब हमारी सरकार बनी तो स्थिति यहां तक पहुंची थी।

The government of India is a continuing entity, I am therefore not referring to it on a Partisan basis.

हमने अपना एक प्रतिनिधिमंडल स्विटजरलैंड भेजा और उस प्रतिनिधिमंडल ने जाकर कहा कि आप हमसे समझौता और सहयोग कीजिए। उन्होंने कहा कि यह चोरी का डेटा है और चोरी के डैटा पर हम समझौता नहीं करते। अक्टूबर में हमने उनसे समझौता कर लिया कि पैसा ले भी गये, लेकिन ऐसे लोगों को सजा तो मिलनी चाहिए, जिन्होंने इस देश का पैसा चोरी करके वहां रखा। हमने स्विट्जरलैंड से चार मुद्दों पर समझौता किया। उसका पहला अंश यह था कि आप केवल चोरी के दस्तावेजों के आधार पर हमारी मदद न करें, लेकिन अगर हम कोई सबूत इकट्ठे करते हैं तो उन सबूतों के आधार पर तो आप हमारी मदद करेंगे या नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम मदद करेंगे। हमने कहा कि फिर क्या टाइम-फ्रेम है जिसमें आप हमारी सहायता करेंगे। आप इन दस्तावेजों को कंफर्म या डिनाई करो कि ये सत्य है या असत्य है। चौथा, भविष्य के लिए हमारे साथ बातचीत शुरू कीजिए कि कोई भी भारतीय अगर स्विट्जरलैंड में एकाउंट खोलता है या कोई ट्रांजेक्शन करता है तो there is an automatic transformation of information to us. Now, this four-point agreement has been put in force; this is an arrangement and we are in regular touch with them. इन 627 में कुछ के केवल नाम थे। अब व्यक्ति का नाम मिल जाए और पता न हो तो कहां ढूंढेंगे? हमने 427 नामों को चिन्हित कर लिया है और उन सब को नोटिस दे दिये हैं, उन सब की पेशी हो रही है। एक-एक करके कई लोगों फौजदारी के मुकदमें अदालतों में डाले गये हैं। जब मीडिया के मित्रों को जानकारी मिलेगी तो पता चलेगा कि उसमें बहुत प्रभावी लोग भी हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि 31 मार्च तक उनकी टैक्स असेसमेंट्स खत्म कर दें और जो-जो उसमें गैर-कानूनी माने जाएंगे, जिन्होंने अपराध किया है, उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमे दायर होंगे। हर सप्ताह मुकदमें दायर हो रहे हैं। निचली अदालत में मुकदमें दायर होते हैं तो देश भर में जहां उनकी असेसमेंट थी वहीं दायर होते हैं। उन 427 में से 250 लोगों ने आकर कबूल कर लिया कि यह हमारा एकाउंट था। यह सारी की सारी कार्रवाई एसआईटी के तहत हो रही है। अब सवाल यह है कि कुछ लोग तो पैसा निकाल कर ले गये, बाकियों का क्या होगा? दुनिया में बीसियों ऐसे केन्द्र और हैं जहां टैक्स हैवन्स में लोग पैसा रखते हैं। आज हमने ''डबल टैक्सेशन अवाएडेंस ट्रीटी'' के तहत 92 देशों के साथ समझौते कर लिये हैं, तिरानवें के साथ भी हस्ताक्षर हो गये हैं तथा सात अन्य के साथ बातचीत चल रही है। टैक्स इंफोर्मेशन का जो फैसला किया है, 15 के साथ पहले से है, 2 के साथ और किया है तथा 29 और ऐसे देश हैं जहां पैसा रखा जाता है उनके साथ हम यह समझौता कर रहे हैं। ये तो केवल दो बैंक लिचनस्टीन और एचएसबीसी स्विटजरलैंड के हुए, लेकिन जो लोग निकट भविष्य में पैसा रखेंगे, तो हम दुनिया के जितने ऐसे देश हैं, उन सब के साथ जो लार्जर कम्युनिटी ऑफ नेशन्स हैं, हम एटोमैटिक ट्रांसमिशन का समझौता कर रहे हैं। हम 48 बड़े देशों में अलह्-एंट्रेंस हैं, जिन्होंने यह तय कर लिया है कि एक दूसरे के साथ जानकारी शेयर करेंगे। कोई भारतीय विदेश में और कोई विदेशी भारत

हमने अपना एक प्रतिनिधिमंडल स्विटजरलैंड भेजा और उस प्रतिनिधिमंडल ने जाकर कहा कि आप हमसे समझौता और सहयोग कीजिए। उन्होंने कहा कि यह चोरी का डेटा है और चोरी के डैटा पर हम समझौता नहीं करते। अक्टूबर में हमने उनसे समझौता कर लिया कि पैसा ले भी गये, लेकिन ऐसे लोगों को सजा तो मिलनी चाहिए, जिन्होंने इस देश का पैसा चोरी करके वहां रखा।

में पैसा रखता है तो उसकी जानकारी शेयर करेंगे। जी-20 ब्रिसबेन में माननीय प्रधान मंत्री ने इसी के लिए प्रयास किया। ओईसीडी में हुआ और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि जो अमरीका ने पटका नाम का कानून बनाया है, जो 2015 से लागू होना है, वह अनिवार्य करता है कि हर देश हमारे साथ फैसला करे कि एक दूसरे के ऐसे खातों की जानकारी शेयर होगी। जो देश ऐसा नहीं करेगा, उसमें जो रैमिटेंस जाएगा, केवल अमरीका से ही नहीं बल्कि उन देशों से भी जिन्होंने हस्ताक्षर किये हुए हैं। उस देश के ऊपर हम तीस परसेंट लगा दैंगे, जिसको विदहोलडिंग टैक्स कहते हैं। कोई एक्सपोर्टर का पैसा आएगा या एफडीआई आएगी या कोई एनआरआई अपने परिवार को पैसा भेजेगा तो तीस परसेंट कट जाएगा, अगर आप ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑफ इनफोर्मेशन के इस कानून पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। उसमें भी कॉनफिडेंशियलिटी क्लॉज़ है। वह कॉनफिडेंशियलिटी क्लॉज़ यह है और वह यह नहीं कहता है कि कभी जानकारी सार्वजनिक नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए हम में से किसी का नाम सामने आ जाता है और जांच में पता चलता है कि यह पैसा जायज़ था। किसी एनआरआई ने रिज़र्व बैंक की अनुमति से बाहर रखा हुआ था तो उस व्यक्ति को बदनाम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नाजायज़ है और सुबूत है तो केस डालिए और नाम सार्वजनिक कर दीजिए। इसलिए विषय यह नहीं है कि जानकारी दी जाए या नहीं दी जाए, विषय यह है कि जानकारी कब दी जाए?

यह सरकार पूरा प्रयास करेगी कि सौ दिन, पांच सौ दिन या हजार दिन, जितना भी समय लगे, जितने भी महीने और वर्ष लगें, जब तक इनमें से आखिरी खाते वाले को पकड़ कर नहीं लाया जाएगा, हम इस प्रयास को नहीं छोड़ने वाले हैं। यह स्वाभाविक है कि राजनैतिक जीवन में हम एक-दूसरे को ताना दे सकते हैं कि आपने ये कहा था, अब आप उसको निभाओ।

कुछ लोग बहुत बहादुर बनते हैं और कहते हैं कि नाम तुरन्त दे दीजिए। ये जितने लोग बिना सुबूत और केस के नाम को सार्वजनिक करने का आग्रह करते हैं, वे अकाउंट होल्डर्स की मदद कर रहे हैं, इससे न स्वीट्ज़रलैंड दस्तावेज देगा क्योंकि आपने उल्लंघन किया है और वह अकाउंट होल्डर कहेगा कि देखिए मेरे खिलाफ तो कोई सुबूत ही नहीं है, मैं तो निर्दोष पाया गया हूं। इसलिए इस पर हमें सम्भल कर चलना है।

अब विषय आया कि भविष्य में या पुराने लोगों को पकड़ते हैं तो टैक्स किस माध्यम से करेंगे? मैं यह ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि हमारे कानून में एक कमज़ोरी है और कमज़ोरी यह है कि जब पैसा पकड़ा जाएगा तो उसको वापस कैसे लाना है? उसको भी अब पूरा करने की जरूरत है। मैं जानता हूं कि एसआईटी भी इस विषय की लचता कर रही है। इनकम टैक्स एक्ट में बाहर वाले का अधिकार नहीं है। मैंने मनी लॉलड्रग एक्ट का अध्ययन किया है, उसमें भी शायद कमज़ोरी है, उसे भी बदलना पड़ेगा। अगर बाहर से नहीं ला सकते हैं तो देश में उतने ही पैसे की उसकी जो सम्पत्ति है उसको कुर्क करने का अधिकार होना चाहिए। इसे इनकम टैक्स में करें या मनी लॉन्ड्रिंग में करें। यूएन कनवेंशन में प्रावधान है कि यहां फौजदारी मुकदमे डालकर सज़ा का डर पैदा करके उस व्यक्ति का धन वापस लाएंगे। राजनैतिक बहस से तो हम कर सकते हैं कि इतने दिनों में लाएंगे और इतना पैसा है, लेकिन इस व्यवस्था को हमारे लिए समझ लेना बहुत आवश्यक है। इसमें एक कठिनाई और भी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्ष 2011 के फैसले में कहा है कि यह कॉनफीडेंशियलटी क्लॉज़ गलत है। दुनिया कहती है कि बिना कॉनफिडेंशियलिटी क्लॉज़ के हम मदद नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कहें कि इन ट्रीटीज़ का सम्मान हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह विषय एसआईटी पर छोड़ दिया है और हम एसआईटी के सामने भी रख रहे हैं।

मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह सरकार पूरा प्रयास करेगी कि सौ दिन, पांच सौ दिन या हजार दिन, जितना भी समय लगे, जितने भी महीने और वर्ष लगें, जब तक इनमें से आखिरी खाते वाले को पकड़ कर नहीं लाया जाएगा, हम इस प्रयास को नहीं छोड़ने वाले हैं। यह स्वाभाविक है कि राजनैतिक जीवन में हम एक-दूसरे को ताना दे सकते हैं कि आपने ये कहा था, अब आप उसको निभाओ। उस पर हम राजनीति की दृष्टि से चलेंगे। लेकिन जो प्रक्रिया हम लोग निभा रहे हैं, उसको पूरा करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सही कानूनी रास्ते पर चल रहे हैं और शीघ्र ही ऐसे लोगों को सज़ा होगी और वे देश में पैसा लाने को मजबूर भी होंगे। मैं इतना ही इस सदन को आश्वासन दिलाना चाहता हूं।■

एकात्म मानववाद

दीनदयालजी उपाध्याय

एकात्म मानववाद भाजपा की मूल विचारधारा है। इस विचार को पं. दीनदयाल उपाध्याय ने 1965 में प्रस्तुत किया था। इस दृष्टि से अगले वर्ष इसके पचास वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम दीनदयालजी द्वारा प्रस्तुत विचार को 'एकात्ममानववाद' पुस्तक से यहां श्रृंखलाबद्ध पुनर्प्रकाशित कर रहे हैं। प्रस्तुत है गतांक में प्रकाशित लेख का शेष भाग-

व्यक्ति के सुख का विचार

सम्पूर्ण समाज या सृष्टि का ही नहीं, व्यक्ति का भी हमने एकात्म एवं संकलित विचार किया है। सामान्यत: तो व्यक्ति का विचार उसके शरीर मात्र के साथ किया जाता है। शरीर सुख को ही लोग सुख समझते हैं, किन्तु हम जानते हैं कि मन में चिन्ता रही तो शरीर सुख नहीं रहता। प्रत्येक व्यक्ति शरीर का सुख चाहता है। किन्तु किसी को जेल में डाल दिया जाय और खूब अच्छा खाने को दिया जाय तो उसे सुख होगा क्या? आनन्द होगा क्या?

पुराना उदाहरण है कि भगवान कृष्ण जब कौरवों के यहाँ सन्धि करने के लिए गए तो दुर्योधन ने उनको बुलाया और कहा, 'महाराज! हमारे यहाँ भोजन करने के लिए आइए।' भगवान कृष्ण दुर्योधन के यहाँ भोजन करने नहीं गये, किन्तु विदुर के यहाँ गये। जब विदुर के यहाँ पहुँचे तो वहां हालत ऐसी हो गई कि विदुर की पत्नी ने अत्यधिक आनन्द के मारे केले के छिलके छील-छील कर भगवान कृष्ण के सामने डाल दिए और गूदा दूसरी तरफ फेंक दिया। भगवान कृष्ण भी उन छिलकों को ही आनन्दपूर्वक खाते रहे। इसलिए लोग कहते हैं- भाई! आनन्द के साथ, सम्मान के साथ यदि रूखी भी मिल जाय तो बहुत अच्छी है, परन्तु अपमान के साथ मेवा भी मिले तो उसे छोड़ना चाहिए। इसलिए मन के सुख का भी विचार करना पड़ता है।

इसी प्रकार बुद्धि का भी सुख है। इसके सुख का भी विचार करना पड़ता है। क्योंकि यदि मन का सुख हुआ भी और आपको बड़े प्रेम से रखा भी तथा आपको खाने-पीने को भी खूब दिया; परन्तु यदि दिमाग में कोई उलझन बैठी रही तो वैसी हालत होती है जैसे पागल की हो जाती है। पागल क्या होता है? उसे खाने को खूब मिलता है; हृष्टपुष्ट भी हो जाता है; बाकी भी सुविधाएँ होती हैं। परन्तु दिमाग की उलझन के कारण बुद्धि का सुख प्राप्त नहीं होता। बुद्धि में भी तो शान्ति चाहिए। इन बातों का हमें विचार करना पड़ेगा।

मानव की राजनीतिक आकांक्षा व तृप्ति

मनुष्य मन, बुद्धि, आत्मा तथा शरीर, इन चारों का समुच्चय है। हम उसको टुकडों में बाँट करके विचार नहीं करते। आज पश्चिम में जो तकलीफें पैदा हुई हैं उनका कारण यह है कि उन्होंने मनुष्य के एक-एक हिस्से का विचार किया। प्रजातन्त्र का आन्दोलन चला तो उन्होंने मनुष्य को कहा कि ''मैन इज ए पॉलिटिकल ऐनिमल'' (Man is a political aimal) अर्थात् मनुष्य एक राजनीतिक जीव है और इसलिए इसकी राजनीतिक आकांक्षा की तृप्ति होनी चाहिए। एक राजा बन करके बैठे और बाकी के राजा नहीं हों, ऐसा क्यों? राजा सबको बनाना चाहिए। इसलिए राजा बनने की आकांक्षा की पूर्ति के लिए उन्होंने सबको वोट देने का अधिकार दे दिया। प्रजातन्त्र में यह अधिकार तो मिल गया, परन्तु बाकी जो अधिकार थे वे कम हो गए। फिर उन्होंने कहा कि वोट देने का तो सबको अधिकार है, परन्तु पेट भरे या न भरे? यदि खाने को नही मिला तो? जब लोगों से कहा गया कि तुम चिन्ता क्यों करते हो? वोट का अधिकार तो तुम्हें है ही। तुम तो राजा हो। राजा बनकर बैठे रहो। राज तुम्हारा है। तो लोगों ने कहा- ''बाबा! इस राज से हमे क्या करना है, अगर हमें खाने को ही नही मिल रहा। पेट को रोटी कही मिल रही तो हमें यह राज नहीं चाहिए। हमें तो पहले रोटी चाहिए।'' कार्लमार्क्स आये और उन्होंने कहा- ''हाँ! रोटी सबसे पहली चीज है। राज तो केवल रोटी वालों का समर्थक होता है। अत: रोटी के लिए लड़ो।'' उन्होंने मनुष्य को रोटीमय बना दिया। पर जो लोग कार्लमार्क्स के रास्ते पर चले, वहाँ का अनुभव यह हुआ कि राज तो हाथ से गया ही और रोटी भी नहीं मिली। किन्तु दूसरी ओर अमरीका है। वहाँ रोटी भी है, राज भी है, इस पर भी सुख और शान्ति नहीं। जितनी आत्म-हत्याएँ अमरीका में होती हैं, और जितने

लोग वहाँ मानसिक रोगों के शिकार रहते हैं, जितने लोग वहाँ पर ट्रंक्विलाइजर (Tranquilizers) खा-खाकर सोने का प्रयत्न करते हैं, उतना दुनिया में और कहीं नहीं होता है। लोग कहते हैं- ''यह क्या समस्या खड़ी हो गई? रोटी मिल गई, राज मिल गया, पर नींद हराम।'' अब वे कहते हैं- 'बाबा नींद लाओ। किसी तरीके से नींद लाओ।' अब वहाँ नींद बड़ी चीज बन गई है और नींद भी आ गई तो तृष्णा उन्हें परेशान कर रही है।

शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा की प्रगति

विचारकों को लग रहा है कि उनकी जीवन-पद्धति में कही-न-कहीं कोई मौलिक गलती अवश्य है, जिससे समृद्धि के बाद भी वे सुखी नहीं। कारण यह है कि वे मनुष्य का पूर्ण विचार नहीं कर पाए। हमारे यहाँ पर इस बात का पूरा विचार किया गया है। इसलिए हमने कहा है कि मानव की प्रगति का मतलब शरीर, मन, बुद्धि व आत्मा-इन चारों की प्रगति है। बहुत बार लोग समझते हैं और इस बात का प्रचार भी किया गया है कि भारतीय संस्कृति तो केवल आत्मा का विचार करती है, बाकी के बारे में वह विचार नहीं करती। यह गलत है। आत्मा का विचार जरूर करते हैं, किन्तु यह सत्य नहीं कि हम शरीर, मन और बुद्धि का विचार नहीं करते। अन्य लोगों नें तो केवल शरीर का विचार किया। इसलिए आत्मा का विचार हमारी विशेषता हो गयी। कालान्तर में इस विशेषता ने लोंगों में एकान्तिकता का श्रम पैदा कर दिया। जिसका विवाह नहीं हुआ वह केवल माँ को प्रेम करता है, किन्तु विवाह के बाद माँ और पत्नी दोनों को प्रेम करता है तथा दोनों के प्रति दायित्व को निभाता है। अब इस व्यक्ति से कोई कहे कि उसने माँ को प्रेम करना छोड़ दिया, तो यह गलत होगा पत्नी भी, जब तक पुत्र नहीं होता, केवल पति को प्रेम करती है, बाद में पति और पुत्र दोनों को प्रेम करती है। इस अवस्था में कभी-कभी अज्ञानवश पति-पत्नी पर यह आरोप लगा देता है कि वह तो अब उसकी चिन्ता ही नहीं करती। किन्तु यह आरोप सही नहीं होता। यदि सही है तो पत्नी अपने कर्त्तव्य से विमुख हो गयी है, ऐसा मानना चाहिए।

हमारी आवश्यकताएँ : चारों पुरुषार्थ

इसी प्रकार हम आत्म की चिन्ता करते हुए शरीर को नहीं भूलता उपनिषद् में तो स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ''नाऽयमात्मा बलहीनन लभ्यः'' दुर्बल (व्यक्ति) आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता। इसी प्रकार की सूक्ति है कि ''शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्'' अर्थात् शरीर धर्म का प्रथम साधन है। दूसरे लोगों से हमारा यही अन्तर है कि उन्होंने शरीर को साध्य माना है, परन्तु हमने उसे साधन समझा है। इस नाते से हमने शरीर का विचार किया है। जितनी भौतिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति का महत्व हमने स्वीकार किया है, परन्तु उन्हें सर्वस्व नहीं माना है। मनुष्य के शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा की आवश्यकताओं की पूर्ति, उसकी विविध कामनाओं, इच्छाओं तथा ईषणाओं की सन्तुष्टि और उसके सर्वांगीण विकास की कृष्टि से व्यक्ति के सामने कर्त्तव्य रूप में हमारे यहाँ चतुर्विध पुरुषार्थ की कल्पना रखी गई है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ का अर्थ उन कर्मों से है जिनसे पुरुषत्व सार्थक हो। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनकी कामना मनुष्य में स्वाभाविक होती है और उनके पालन से उसको आनन्द प्राप्त होता है। इन पुरुषार्थों का भी हमने संकलित विचार किया है। यद्यपि मोक्ष को परम पुरुषार्थ माना है, तो भी अकेले उसके सेवन से मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता। वास्तव में तो अन्य पुरुषार्थों की अवहेलना करने वाला कभी मोक्ष का अधिकारी नहीं हो सकता। इसके विपरीत शेष पुरुषार्थों को लोक संग्रह के विचार से, निष्काम-भाव से करने वाला व्यक्ति कर्म बन्धन से छूटकर मोक्ष का अधिकारी होगा।

'अर्थ' के अन्तर्गत आज की परिभाषा के अनुसार राजनीति और अर्थ-नीति का समावेश होता है। पुरानी परिभाषा में 'दण्डनीति और वार्ता' अर्थ के अन्तर्गत आती है। 'काम' का सम्बन्ध मानव की विभिन्न कामनाओं की पूर्ति की तृप्ति से है। 'धर्म' में उन सभी नियमों, व्यवस्थाओं, आचरण संहिताओं तथा मूलभूत सिद्धान्तों का अन्तर्भाव होता है जिनसे अर्थ और काम की सिद्धि हो।

इस प्रकार धर्म आधारभूत पुरुषार्थ है, किन्तु फिर भी तीनों अन्योन्याश्रित तथा एक-दूसरे के पूरक और पोषक हैं। धर्म से अर्थ की सिद्धि होती है। यदि व्यापार भी करना हो तो मनुष्य को ईमानदारी, संयम, त्याग, तपस्या, अक्रोध, क्षमा, धृति, सत्य आदि धर्म के लक्षणों का निर्वाह करना पड़ेगा। बिना इन गुणों के पैसा नहीं कमाया जा सकता। साधन के रूप में तो धर्म को मानना ही पड़ेगा।

अमरीका वालों ने कहा- 'व्यापार के मामले में ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है (Honesty is the best business policy)।'

यूरोप के लोगों ने कहा- 'ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है (Honesty is the best policy)।'

हमारा उनसे एक कदम आगे चलकर कहना है कि

'ईमानदारी नीति नहीं अपितु सिद्धान्त है (Honesty is not a policy but a principle)।'

अर्थात् धर्म में हमारा विश्वास केवल उसकी साधनता के कारण नहीं, अपितु स्वयंभू है। राज्य का आधार भी हमने धर्म को माना है। अकेली दण्डनीति राज्य को चला नही सकती। समाज में धर्म न हो तो राज्य नहीं टिक सकेगा। काम पुरुषार्थ भी धर्म के सहारे ही सधता है। भोजन उपलब्ध होने के उपरान्त कब, कहाँ, कितना, कैसा और कैसे उसका उपयोग हो यह तो धर्म ही निश्चित करेगा। अन्यथा रोगी ने यदि स्वस्थ व्यक्ति का भोजन किया और स्वस्थ व्यक्ति ने रोगी का तो दोनों का ही अकल्याण होगा। मनुष्य की मनमानी को रोकने, उसके स्वैराचरण पर प्रतिबन्ध लगाने तथा प्रेय के पीछे श्रेय को न भूलने देने में धर्म ही सहायक होता है। अत: हमारे यहाँ धर्म का विशेष महत्व है।

धर्म महत्वपूर्ण है, परन्तु यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अर्थ के अभाव में धर्म नहीं टिक पाता। एक सुभाषित है कि-

बुभुक्षित: कि न करोति पापम्, क्षीणा नरा निष्करुणा: भवन्ति। अर्थात् भूखा सब पाप कर सकता है। विश्वामित्र जैसे ऋषि ने भी भूख से 'पीडित होकर शरीर धारण करने के लिए चाण्डाल के घर में चोरी करके कुत्ते का जूठा मांस खाया था। अत: हमारे यहाँ आदेश है कि अर्थ का अभाव नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि वह धर्म का द्योतक है। इसी प्रकार दण्डनीति का अभाव अर्थात् अराजकता ही धर्म के लिए हानिकारक होती है। उसमें 'मात्स्य-न्याय' काम करने लगता है। अत: राज्य की स्थापना धर्म के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

अर्थ के 'प्रभाव' से अनर्थ की सम्भावना

अर्थ के अभाव के समान ही अर्थ का प्रभाव भी धर्म का घातक होता है। प्रभाव का अर्थ आधिक्यमात्र नहीं है। जब व्यक्ति और समाज में अर्थ साधन न रहकर साध्य बन जाए तथा जीवन की सभी विभूतियाँ अर्थ से ही प्राप्त हों तो वहाँ अर्थ का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है और वह अर्थ-संचय के लिए नानाविध पाप करता है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति के पास अधिक धन हो उसके विलासी बन जाने की सम्भावना रहती है। जिस व्यक्ति को अर्थ के सदुपयोग का ज्ञान नहीं होता वहाँ भी अर्थ का प्रभाव होता है। जहाँ 'गौण अर्थ' अर्थात् मुद्रा तथा उपभोक्ता वस्तुओं के लिए लगने वाली उत्पादक वस्तुओं का आधिक्य हो वहाँ भी अर्थ का प्रभाव होता है। इन सभी प्रकार कें अर्थ के प्रभावों को बचाना चाहिए। इसके लिए शिक्षा, संस्कार, दैवी सम्पद्युक्त व्यक्तियों का निर्माण तथा अर्थव्यवस्था का उपयुक्त ढाँचा, सभी का सहारा लेना जरूरी होता है। दण्ड-नीति

अर्थ के अन्तर्गत दण्ड-नीति भी आती है। उसका 'प्रभाव' भी धर्म के लिए हानिकारक होता है। राजा को बताया है कि न तो 'क्षीणदण्ड' होना चाहिए, और न 'उग्रदण्ड' होना चाहिए, अपितु 'मृदुदण्ड' होना चाहिए। यदि राजा दण्ड-नीति का अत्यधिक सहारा लेता है तो प्रजा में विद्रोह की भावना पैदा हो जाती है। जब धर्मभाव के स्थान पर दण्ड ही प्रजा के आचरण का नियामक बन जाए तो दण्डनीति का 'प्रभाव' हो जाता है तथा धर्म का ह्रास होने लगता है। निरंकुश राजाओं के शासन में धर्म की ग्लानि का यह प्रमुख कारण है।

राज्य की निरंकुशता

राज्य जब सब प्रकार की विभूतियों को स्वाधीन कर लेता है तब भी उसका प्रभाव पैदा होकर धर्म की हानि होती है। राज्य की शक्ति और क्षेत्र अमर्यादित हो गए तो सम्पूर्ण जनता राज्यमुखापेक्षी बन जाती है। वहाँ राज्य का प्रभाव हो जाता है। राज्य में कर्तव्य भावना के स्थान पर आसक्ति पैदा हो जाती है। ये सब प्रभाव के लक्षण हैं। इन अवस्थाओं में धर्म को धक्का लगता है। अत: अर्थ का दोनों ही दृष्टि से प्रभाव नहीं होने देना चाहिए।

काम का भी इसी प्रकार विचार किया गया है। काम पुरुषार्थ की ओर कतई ध्यान नही दिया गया तो धर्म की हानि होगी। बिना भोजन के धर्म नहीं चल सकता। मन को सन्तोष देने वाली ललितकलाओं, यज्ञ, योगादि कर्मो की अवहेलना हुई तो धर्म का पालन करने वाले संस्कार नहीं होंगे। मानस विकृत रहेगा तथा धर्म की हानि होगी। दूसरी ओर रोम के ग्लटन्स (Gluttons) की भाँति हम पेटू और विलासी बन गए अथवा ययाति की भाँति काम मोहित होकर अपने सभी कर्तव्यों को भूल गए, तो भी धर्म की हानि होगी। अत: निर्वाह करना चाहिए।

इस प्रकार हमने व्यक्ति के विचार किया है। उसके शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा सभी का विकास करने का उद्देश्य रखा है। उसकी सभी भूखों को मिटाने की व्यवस्था की है। किन्तु यह ध्यान रखा है कि एक भूख को मिटाने के प्रयत्न में दूसरी भूख न पैदा कर दें अथवा दूसरे के मिटाने का मार्ग बन्द न कर दें। इस हेतु चारों पुरुषार्थो का संकलित विचार हुआ है। यह पूर्ण मानव की, एकात्म मानव की कल्पना है जो हमारा आराध्य तथा हमारी आराधना का साधन दोनों ही है। ■

अटल जी के 90वां जन्मदिन पर विशेष : 25 दिसम्बर 2014

''अंधकार छंटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा''

देश 25 दिसम्बर 2014 को अटलजी का 90वां जन्मदिवस मनाने जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उनके जन्म दिवस 25 दिसम्बर को 'सुशासन दिवस' के रूप में पूरे देश में मनाया जाएगा। अटल जी 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय प्रथम अध्यक्ष बने थे। जिन हालात में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, वे अपूर्व थे। राष्ट्रहित में जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हुआ। फिर बाद में जनता पार्टी ने एक प्रस्ताव पारित कर उन सभी को निष्कासित करने का निर्णय लिया था जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे। यानी दोहरी सदस्यता का मुद्दा उछाला गया। जनसंघ से जुड़े नेताओं ने नई पार्टी बना कर निर्माण प्रक्रिया फिर से आरम्भ की। बम्बई (अब मुम्बई) में आयोजित राष्ट्रीय परिषद में अटल जी का 28-30 दिसम्बर 1980 का अध्यक्षीय भाषण ने पार्टी की नई स्फूर्ति को जागृत किया और पूर्व जनसंघ के कार्यकर्ताओं को नया संकल्प देते हुए या मां भारती के चरणों में स्वयं को समर्पित करने की प्रेरणा दी। यह सचमुच एक ऐतिहासिक भाषण था।

इस भाषण में उन्होंने कहा था कि ''कमल फिर से खिलेगा''। 1996, 1998, 1999 में कमल का फूल खिल उठा जब केन्द्र में राजग सरकार की स्थापना हुई। आज कमल का फूल पूरी तरह से खिल उठा है, भाजपा को 2014 के चुनावों में लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया है। अटलजी भविष्य को देखने में सक्षम थे, वह सचमुच दूरदृष्टा और राजनेता हैं। हम उनका यह प्रथम अध्यक्षीय भाषण यहां पुन: प्रकाशित कर रहे हैं:-

स्वागताध्यक्ष जी, प्रतिनिधि बंधुओं, बहनों और मित्रों,

एक अवसर और एक चुनौती

आज हम यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए एकत्र हुए हैं। मुझे निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित कर आपने मेरे प्रति जो स्नेह और विश्वास प्रकट किया है उसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूं। मैं जानता हूं कि इस नाजुक घड़ी में किसी राजनीतिक दल का नेतृत्व ग्रहण करना कितना टेढ़ा काम है। मैं यह भी जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष पद अलंकार की वस्तु नहीं है। वस्तुत: यह पद नहीं, दायित्व है; प्रतिष्ठा नहीं, परीक्षा है; अधिकार नहीं, अवसर है; सत्कार नहीं चुनौती है। परमात्मा से प्रार्थना है कि वह मुझे शक्ति तथा विवेक दे जिससे मैं इस दायित्व को ठीक तरह से निभा सकूं।

नई पार्टी क्यों ?

भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ, इसके ब्यौरे में मैं नहीं जाना चाहता। किंतु इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि हम जनता पार्टी से खुशी से अलग नहीं हुए। आरंभ से अंत तक हम निरंतर इसी दिशा में प्रयत्नशील रहे कि पार्टी की एकता बनी रहे। हमें वह शपथ याद थी जो हमने पार्टी की एकता बनाए रखने के लिए राजघाट पर लोकनायक जयप्रकाश जी के समक्ष ली। परंतु दोहरी सदस्यता की समस्या को समस्या बनाकर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की गई कि हमारे सामने जनता पार्टी से अलग होने के अतिरिक्त कोई और सम्मानपूर्ण विकल्प नहीं रह गया।

जिन्होंने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की उनके इरादे क्या थे, आज इस में जाने से कोई लाभ नहीं होगा। परंतु यह उल्लेखनीय है कि दोहरी सदस्यता के प्रश्न को एक बहाना मानने वालों में ऐसे बहुत से लोग थे जिनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कभी भी और किसी भी रूप में संबंध नहीं रहा। उनमें से अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के निर्माताओं में से है।

पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता

9 महीनों के अल्प समय में ही भारतीय जनता पार्टी को समूचे देश में जो व्यापक तथा प्रबल समर्थन प्राप्त हुआ है उससे हमारे अलग दल बनाने के निर्णय की पुष्टि ही हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या 25 लाख से ऊपर है तथा इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो पुराने जनसंघ में नहीं थे। फिर भी हमारे कुछ विरोधी, जिनमें प्रधानमंत्री अग्रणी हैं, यह कहते नहीं थकते कि 'भारतीय जनता पार्टी' पुराने जनसंघ का ही नया नाम है। देश के सभी भागों तथा समाज के सभी वर्गों में भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से परेशान और भविष्य में पार्टी की भारी संभावनाओं से भय खाकर ही ये लोग सच्चाई पर पर्दा डालने में लगे हैं।

अधुरे स्वप्न को साकार करने का प्रयास

लोकनायक जयप्रकाश के आह्वान पर बनी जनता पार्टी टूट गई। पर लोकनायक ने इस महान भारत देश के जिस रूप का स्वप्न देखा था हम उसे नहीं टूटने देंगे। उनका स्वप्न, उनकी साधना, उनका संघर्ष, कुछ जीवन मूल्यों में उनकी अडिग आस्था, हमारी अनमोल विरासत के अंग हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकनायक जयप्रकाश के अधूरे कार्य को पूरा करने को कृतसंकल्प है।

मूल्याधिष्ठित राजनीति

आज हमारा देश बहुआयामी संकट के बीच गुजर रहा है। निरंतर बढ़ती महंगाई, बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति, दैनिक खपत की आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि में कठिनाई, सांप्रदायिक दंगों की उग्रता तथा अवधि में वृद्धि, अधिकाधिक सामाजिक तनाव तथा हिंसा, हरिजनों, गिरिजनों, स्त्रियों तथा अन्य कमजोर वर्गों पर बढ़ता अत्याचार, पूर्वांचल की विस्फोटक परिस्थिति, ये इस संकट के कुछ आयाम हैं।

नैतिक संकट

इन समस्याओं का सामना करने का जिन पर दायित्व है, वे सत्ता की शतरंज पर मोहरे बैठाने में लगे हैं तथा इन का समाधान करने में असमर्थ हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि मूलत: हमारा संकट एक नैतिक संकट है। हमारे सार्वजनिक जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप यह है कि नैतिक मूल्यों का स्थान स्वार्थ-सिद्धि एवं स्वार्थ सिद्धि के साधन के रूप में सत्ता प्राप्ति ने ले लिया है।

सार्वजनिक जीवन में पतनावस्था

1969 में राष्ट्रपति पद के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवार, जिनका नामांकन-पत्र स्वयं प्रधानमंत्री ने दाखिल किया था, को हराने के लिए अपनाए गए अनैतिक तरीकों से जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई, वह समय बीतने के साथ अधिकाधिक व्यापक और बलवती होती गई। 1975 में घोषित आपात स्थिति किसी अंतरबाह्य संकट का सामना करने के लिए नहीं, बल्कि सत्ता में बने रहने के लिए ही थी। जनता शासन में न्यायालयों में उपद्रव, विमान का अपहरण जैसे गंभीर अपराधों को प्रोत्साहन देना, डराने-धमकाने के अन्य तरीके अपनाना, बड़े पैमाने पर दलबदल कराने की साजिश, इसी प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। 1980 के चुनाव में असामाजिक तत्त्वों का खुला उपयोग तथा थोक वोट प्राप्त करने के लिए सांप्रदायिक, जातीय तथा क्षेत्रीय भावनाओं को उकसाने के प्रयत्नों को भी इसी संदर्भ में समझा जा सकता है।

दोहरा मानदण्ड

नैतिकता का दोहरा मानदण्ड, इसी प्रक्रिया का एक पक्ष है, जो सत्ता में है या सत्ताधारियों के कृपापात्र हैं, उनके निकट हैं, उनके संबंधी हैं, उनके लिए एक मानदण्ड, औरों के लिए दूसरा मानदण्ड। जनता शासन के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने कृपा-पात्रों और संबंधियों के विरुद्ध लगाए गए अभियोगों को, संथानम कमेटी की सिफारिशों की परवाह न करते हुए, न्यायिक विचार के बिना अस्वीकार कर दिया। इसके विपरीत जनता शासन में प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने संबंधियों का मामला न्यायिक विचार के लिए भेजा। वास्तव में जनता शासन के 28 महीनों में ही इस प्रक्रिया की रोकथाम की दिशा में कुछ करने का प्रयत्न किया गया।

इस प्रकार की प्रक्रिया केवल शासक वर्ग तथा राजनीतिक दलों को प्रभावित करके नहीं जाती। वह समूचे समाज, नौकरशाही, उद्योगपतियों, व्यापारियों, यहां तक कि आम लोगों को भी, अपने चंगुल में लपेट लेती है। स्वार्थसिद्धि तथा जैसे भी हो अपना काम बना लेने की हवा चल पड़ती है। परिणामत: राष्ट्र की नैतिक शक्ति का ह्रास हो जाता है और राष्ट्र संकटों का सफलतापूर्वक सामना करने की क्षमता खो बैठता है।

नैतिक मूल्यों की पुनः स्थापना

वर्तमान संकट पर विजय पाने की पहली शर्त यह है कि हमारा सार्वजनिक जीवन नैतिक मूल्यों पर आधारित हो। हमें इन मूल्यों को ढूंढने के लिए देश के बाहर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। भारत के जन-जीवन की परंपरा में ही इन मूल्यों की जड़ें विद्यमान हैं। संप्रदाय, धर्म, जाति, भाषा तथा क्षेत्र की सीमाओं से ऊपर उठकर आम भारतीयों का जीवन जिन मूल्यों से जुड़ा हुआ रहा है, जैसे सहिष्णुता, सादगी, संतोष, परिश्रम, भाईचारे की भावना, उन्हीं को आधार बनाकर हमें नए समाज की रचना करनी है। आधुनिक परिस्थितियों के संदर्भ में जनजीवन का पुराना रूप बदलना वांछनीय है। पंडित नेहरू ने विज्ञान तथा टेकनोलोजी के उपयोग पर बल देकर विकास की जो दिशा दिखाई उससे राष्ट्र की समृद्धि बढ़ी, किंतु वह समृद्धि कुछ लोगों तक ही सीमित रह गई। विषमता में वृद्धि हुई तथा अमीर और गरीब के बीच की खाई और अधिक चौड़ी हो गई। इस विकृति को दूर करने के हेतु भारतीय परंपरा के मूल्यों का आधार बनाकर आगे चलना है और व्यक्ति को, विशेषकर दुर्बलतम व्यक्ति को, विकास प्रक्रिया का केन्द्र बिन्दु बनाना है। गांधी, जयप्रकाश तथा दीनदयाल प्रभूति मनीषियों ने प्रगति के इसी रूप का प्रतिपादन किया था। इसी दृष्टिकोण से जनता शासन में अंत्योदय तथा काम के बदले अनाज जैसी योजनाएं हाथ में ली गई थीं।

इस प्रकार के समाज का निर्माण जो शोषण तथा भेदभाव रहित तथा कुंछ जीवन मूल्यों पर आधारित हो, केवल बड़ी-बड़ी बातें करने तथा महात्मा गांधी का नाम रटने से नहीं हो सकता। इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। गरीब किसानों, श्रमिकों, हरिजनों, गिरिजनों तथा अन्य शोषित वर्गों को संगठित करना होगा। इनकी संगठित शक्ति द्वारा ही इस प्रकार के समाज का निर्माण हो सकेगा। महात्मा गांधी ने जन शक्ति को जगाकर तथा संगठित करके ही विदेशी सरकार के विरुद्ध सफल संघर्ष किया था।

सिद्धांत आधारित राजनीति

हम जनता को तभी संगठित कर सकेंगे, हमारी बात वह तभी सुनेगी जब कि हम उसके मन में अपनी विश्वसनीयता स्थापित कर सकें, उसे हम यह विश्वास दिला सकें कि हमारा उद्देश्य केवल स्वार्थसिद्धि और सत्ता हथियाना नहीं है, हमारी राजनीति कुछ मूल्यों, कुछ सिद्धांतों पर आधारित है।

गांधीवादी समाजवाद

भारतीय जनता पार्टी ने सोच समझकर गांधीवादी समाजवाद को स्वीकार किया है। स्वयं गांधी जी अपने विचारों को किसी वाद का रूप देने के पक्ष में नहीं थे, किंतु उन्होंने जीवन को न केवल उसकी समग्रता में देखा था, बल्कि आधुनिक समस्याओं के हल के बारे में एक समन्वित दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया था।

उन्होंने मनुष्य का विचार मात्रा आर्थिक इकाई के रूप में नहीं किया। सभी प्राचीन मनीषियों की भांति महात्मा जी भी मनुष्य की भौतिक और आध्यात्मिक दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति को अपना लक्ष्य बनाते हैं। गांधी जी से पहले स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्मिक समाजवाद की बात कही थी। गीता में साम्ययोग को चर्चा है। ईशवास्य उपनिषद में किसी दूसरे के धन को ललचायी आंखों से न देखने का निर्देश एक ऐसी समाज रचना की ओर संकेत करता है जो 'अपरिग्रह' पर आधारित होगी। 'सबै भूमि गोपाल' की के पीछे भी यही भावना है। यज्ञ में हर आहुति के बाद 'इदन्नमम्' (यह मेरा नहीं है) का उच्चारण व्यक्ति के मन पर यह छाप छोड़ने के लिए ही है कि आवश्यकता से अधिक का संचय नहीं करना चाहिए।

मानव मूल्यों की स्वीकृति

महात्मा और मार्क्स द्वारा प्रणीत समाजवाद में मौलिक अंतर है। गांधीवादी समाजवाद पुरातन काल से विकसित मानवीय मूल्यों से प्रारंभ करता है और फिर उन्हीं मूल्यों के आधार पर आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण पर बल देता है। इसके विपरीत मार्क्स की विचारधारा में मानवीय मूल्य सामाजिक संबंधों, भौतिक परिस्थितियों और उत्पादन के ढंगों पर निर्भर करते हैं।

गांधीवाद और मार्क्सवाद दोनों मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को समाप्त करने का दावा करते हैं, किंतु मार्क्सवाद बिना अपनी चौखट को लांघे यह नहीं बता सकता कि वह ऐसा क्यों करना चाहता है। गांधीवाद इस आधारभूत मान्यता से ही प्रारंभ करता है कि मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण मानवीय मूल्यों की अवहेलना है।

....क्रमशः

'सबका साथ, सबका विकास' से अलग-थलग पड़ा पाकिस्तान

✍ डा. शिव शक्ति बक्सी

भारत के गणतंत्र दिवस 2015 के अवसर पर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा मुख्य अतिथि बनने जा रहे हैं। 21 नवम्बर 2014 की सायं को प्रधानमंत्री मोदी को जैसे ही औपचारिक पुष्टि प्राप्त हुई, उन्होंने ट्विटर पर अपना यह संदेश भेजा कि इस गणतंत्र दिवस पर हमें उम्मीद है कि राष्ट्रपति ओबामा पहले अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे जो मुख्य अतिथि बनेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के ट्विटर पर लिखा गया कि ''नरेन्द्र मोदी के आमंत्रण पर राष्ट्रपति ओबामा मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय गणतंत्र दिवस पर भाग लेने के लिए भारत की यात्रा करेंगे।'' व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर प्रेस सचिव ने यह बयान लिखा कि अमेरीका के राष्ट्रपति को पहली बार गणतंत्र दिवस पर पहले राष्ट्रपति के रूप में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। गणतंत्र दिवस पर ओबामा की मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थिति को राजनयिक और भारत-अमेरिका द्विपक्षीय सम्बन्धों में बहुत बड़ी घटना माना जा रहा है।

1950 से भारत की गणतंत्र दिवस पर विभिन्न राष्ट्रों के प्रमुखों को आमंत्रित करने की परम्परा रही है। परन्तु, यह पहली बार है जब अमेरीकी राष्ट्रपति इस अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। इस वर्ष सितम्बर में अमेरीका की यात्रा के पश्चात नरेन्द्र मोदी म्यामांर में जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान छह सप्ताहों में दूसरी बार बराक ओबामा से मिले जहां दोनों ने विचारविमर्श किया और अमेरीकी राष्ट्रपति ने उन्हें 'Man of action' (अर्थात काम करने वाला व्यक्ति) कह कर सम्बोधित किया। यह महत्वपूर्ण है कि मोदी ने ओबामा के साथ अच्छी व्यक्तिगत अंतरंगता बनाई है और दोनों ही द्विपक्षीय सम्बन्धों को सुधारते हुए कई प्रकार बहुपक्षीय बातचीत में लगे हुए हैं। इसके उदाहरण में दोनों देशों के बीच डब्ल्यूटीओ पर गतिरोध टूटा जहां भारतीयों के चिंता के विषयों पर समुचित समाधान करने का प्रयास हो रहा है। ओबामा द्वारा मोदी के आमंत्रण को स्वीकार करने से विभिन्न विशेषज्ञ इसे भारी राजनयिक जीत माने रहे हैं। यह अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्राथमिकताओं को बदलने का भी संकेत माना जा रहा है और इससे विश्व स्तर पर भारत का महत्व बढ़ता भी दिखाई दे रहा है।

जहां एक तरफ विशेषज्ञों द्वारा इसे मोदी और ओबामा के बीच बढ़ती अंतरंगता के रूप में देखा जा रहा है जो चीन और अमेरीका में संतुलन बनाने का काम करेगा, वहीं राजनयिक क्षेत्रों में पाकिस्तान के बारे में कोई चर्चा तक नहीं की जा रही है। अब प्रश्न है कि क्या पाकिस्तान को अमेरीका महत्व दे रहा है? अभी तक दक्षिण एशिया की अपनी नीति में अमेरिका पाकिस्तान और भारत को जोड़ कर देखा करती थी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा अधिवेशन में पाकिस्तान प्रधान मंत्री नवाज शरीफ ने काश्मीर का मुद्दा उठाने की फिर कोशिश की, जिसकी पूरी तरह से उपेक्षा हुई क्योंकि जब वे बोले उस समय लगभग पूरा हाल खाली पड़ा था। इसके विपरीत, नरेन्द्र मोदी के सम्बोधन पर बड़ी संख्या में प्रतिनिधि मौजूद थे जो उनके शांति, सद्भावना और विकास के विचारों से अधिक प्रभावित हुए। वाशिंगटन में मोदी का भव्य स्वागत हुआ और उन्होंने भारतीयों की भारी जनसमूह को सम्बोधित किया। 'पाकिस्तान टूडे' के सम्पादक आरिफ आजमी ने लिखा है कि वास्तव में

ओबामा द्वारा मोदी के आमंत्रण को स्वीकार करने से विभिन्न विशेषज्ञ इसे भारी राजनयिक जीत माने रहे हैं। यह अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्राथमिकताओं को बदलने का भी संकेत माना जा रहा है और इससे विश्व स्तर पर भारत का महत्व बढ़ता भी दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ विशेषज्ञों द्वारा इसे मोदी और ओबामा के बीच बढ़ती अंतरंगता के रूप में देखा जा रहा है जो चीन और अमेरीका में संतुलन बनाने का काम करेगा, वहीं राजनयिक क्षेत्रों में पाकिस्तान के बारे में कोई चर्चा तक नहीं की जा रही है।

पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र और दक्षिणी एशिया क्षेत्र में अकेला पड़ता जा रहा है। इस वास्तविक सच्चाई का सीधा उदाहरण नरेन्द्र मोदी की अमेरीका यात्रा से मिलता है। वह आगे लिखते हैं कि जिस ढंग से वाशिंगटन ने मोदी का आतंकवाद पर समर्थन किया है, वह हमारे नीति-निर्माताओं के लिए चिंता का विषय है। वाशिंगटन में मोदी यात्रा सम्पन्न होने पर जारी वक्तव्य में पाकिस्तान को सीधे-सीधे फंसाया गया है। असाधारण कड़े शब्दों में लिखे संयुक्त और एकजुट प्रयासों की बात कही गई है जिसमें आतंकवादियों और अपराधियों के नेटवर्क वाले सुरक्षित हैवन को जैसे अलकायदा, लश्करे तैय्यबा, जैश-ए-मोहम्मद, डी-कम्पनी और हक्कानी नेटवर्क को तबाह करने की बात है।

हाल ही में 18वां सार्क शिखर सम्मेलन काठमांडू में सम्पन्न हुआ, जिसमें देखा गया कि पाकिस्तान इस क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं में रूकावट डालने का प्रयास कर रहा था। यह कोई नई चाल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो सार्क के शुरू होने से ही कोशिश करता रहा है कि वह इस फोरम को गैर-प्रभावी बना कर भारत-पाकिस्तान विवाद में फंसा दे। परन्तु इस बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने न केवल पाकिस्तान को अलग-थलग किया बल्कि यह भी स्पष्ट संदेश दिया कि यदि पाकिस्तान बिगडैल की भूमिका निभाता है तो भी हम अन्य सदस्यों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। पाकिस्तान द्वारा आखिरी क्षण पर भी तीन निर्णायक समझौतों से पीछे हटने के प्रयास को इसी दिशा में देखा जा सकता है, जबकि यह पूरी तरह तैयार हो चुके थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सार्क में नई ऊर्जा का संचार किया, पहले तो उन्होंने सभी सार्क देशों को शपथ-ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया और फिर उन्होंने नेपाल और भूटान की यात्रा और बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान को सभी द्विपक्षीय मुद्दों पर अपने साथ लेकर आए। उनके बहुत से भाषणों में उन्होंने सार्क को गरीबी हटाने और क्षेत्र में विकास को अधिक गति देने के लिए सार्क को प्राथमिकता देने की बात कही। यह एक प्रकार से भारत की विजय थी जब सार्क सदस्यों ने ऊर्जा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए और दो अन्य समझौतों-यात्रियों के नियमन के लिए 'सार्क मोटर व्हेकिल सम्मीट' और रेलवे पर 'कार्गो व्हेकिलुर समझौता'- पर 90 दिनों का समय दिया जिन्हें 2016 में पाकिस्तान में होने वाले 19वें शिखर सम्मेलन में स्वीकार किया जाना है। भारत ने बुद्धिमत्ता से काम लिया, जो अभी तक भारत-पाकिस्तान का मंच देखा जाता था अब वह क्षेत्रीय आकांक्षाओं और आशाओं का मंच बन गया। पाकिस्तान और भी अलग-थलग पड़ गया जब शेष सार्क देशों बनाम पाकिस्तान का वातावरण काठमांडू में बनने लगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने सार्क में नई ऊर्जा का संचार किया, पहले तो उन्होंने सभी सार्क देशों को शपथ-ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया और फिर उन्होंने नेपाल और भूटान की यात्रा और बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान को सभी द्विपक्षीय मुद्दों पर अपने साथ लेकर आए। उनके बहुत से भाषणों को उन्होंने सार्क को गरीबी हटाने और क्षेत्र में विकास को अधिक गति देने के लिए सार्क को प्राथमिकता देने की बात कही।

स्पष्ट है कि पाकिस्तान को ओबामा द्वारा मुख्य अतिथि बनना तथा भारत का निमंत्रण स्वीकार कर भारत के गणतंत्र दिवस पर पहुंचना अच्छा नहीं लगा। जहां तक राष्ट्रपति की यात्रा सम्बन्ध है, पाकिस्तान भी भारत की तरह बराबरी का व्यवहार करने की मांग करता रहा है। इससे पूर्व राष्ट्रपति क्लिंटन और राष्ट्रपति बुश ने अपने भारत यात्रा के दौरान थोड़े समय के लिए पाकिस्तान में भी रूके थे। ओबामा ने 2010 में अपनी भारत यात्रा के दौरान इस परम्परा को तोड़ा था तब उन्होंने 2011 में पाकिस्तान की यात्रा करने की बात कही थी जो पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा-बिन-लादेन के मारे जाने के कारण नहीं हो सकी। भारत में ओबामा की यात्रा की खबर देखते हुए पाकिस्तान ने फिर से ओबामा और नवाज शरीफ के बीच फोन पर बातचीत में काश्मीर का मुद्दा उठाया, परन्तु व्हाइट हाउस की विज्ञप्ति में फोन काल के दौरान इस बात का कोई जिक्र नहीं था बल्कि इसके बजाय इस क्षेत्र और अफगानिस्तान के सम्बन्धों में आतंकवाद और उग्रवादियों का उल्लेख था।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पाकिस्तान का लगतार अलग-थलग पड़ना मोदी की राजनयिक विजय माना जा रहा है। यह रणनीति सफल दिखाई पड़ती है क्योंकि भारत को प्रगतिशील और विकासवर्ती नीतियों के पैरोकार रूप में देखा जा रहा है। सीमापार से उकसाये जाने के बाद

भी प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का नाम लेने से परहेज किया है। भारतीय बलों ने पहली बार पाकिस्तान को पलट कर उसी की भाषा में जवाब दिया है। शपथ-ग्रहण समारोह के दौरान सार्क देशों को आमंत्रित करने से प्रधानमंत्री और नवाज शरीफ के बीच भारत यात्रा ने आशा का माहौल बनाया था, परन्तु पाकिस्तान का काश्मीर अलगाववादियों से बात करने के कारण माहौल खराब हुआ है। इसके फलस्वरूप सचिव स्तर की वार्ता रद्द कर दी। तब से पाकिस्तान इस विषय पर माफी तक नहीं मांगी है बल्कि भारत से ही बातचीत की पहल की अपेक्षा करता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके जाल में फंसने से इंकार कर सही काम किया और भारत को राजनयिक स्तर पर पाकिस्तान से दूरी बनाए रखी तथा और भी कड़ाई से सीमा-पार फायरिंग का जवाब दिया। काश्मीर के लोगों ने जम्मू-कश्मीर विधान सभा चुनावों में बड़ी संख्या में मतदान कर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, जहां चुनाव बड़े शांति ढंग से सम्पन्न हुए।

भारत न केवल विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि विश्व में वह उभरता हुआ बड़ी आर्थिक ताकत भी है जो विश्व स्तर पर विभिन्न मोर्चों पर नेतृत्व की भूमिका निभाने की क्षमता रखता है। कुछ निहित स्वार्थों द्वारा भारत को पाकिस्तान से जोड़ भारत के प्रगति-पथ में बाधा डालने का प्रयास होता रहा है। भाजपा-नीत-राजग सरकार ने निरंतर इस जाल से बचना चाहा है और अन्तर्राष्ट्रीय जगत में स्वतंत्र स्थान बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी का 'सबका साथ, सबका विकास' मंत्र का कार्यान्वयन विश्व स्तर पर किए जाने से भारत का इरादा साफ हुआ है कि वह प्रत्येक राष्ट्र को विकास और समृद्धि की राह पर देखना चाहता है, विशेष कर सार्क देशों के क्षेत्र में। भारत आने से पूर्व वाशिंगटन में अमेरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन केरी ने कहा था- ''नई भारत सरकार की योजना 'सबका साथ, सबका विकास', सभी देशों के लिए एक ऐसी दूरदृष्टि है जिसका हम समर्थन करते हैं।''

विकास एजेण्डा के समावेशी विकास और पड़ौसी देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति ने सभी का दिल जीत लिया है और नेपाल इसका ज्वलंत उदाहरण है।

पाकिस्तान की एक मात्र नीति है कि भारत का विभिन्न मंचों पर विरोध किया जाए- अब यह नीति अर्थहीन होती जा रही है, क्योंकि इसका विकास के राजनीति के नए युग से कुछ लेना-देना नहीं है। यह कहना ठीक होगा कि 'सबका साथ, सबका विकास' उदयमान अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और विश्व राजनीति की बदलती स्थितियों में प्रभावशाली ढंग से पाकिस्तान को अलग-थलग करती जा रही है। ■

भाजपा की राजस्थान के नगर निगम चुनावों में भारी जीत

राजस्थान में भाजपा ने राज्य के नगर निगम चुनावों में भारी जीत प्राप्त कर 46 नगर निगम चुनावों में से 27 पर कब्जा कर लिया है, जहां 22 नवम्बर को चुनाव हुए। छह नगर निगमों में से भाजपा ने 5 में विजय प्राप्त की। जयपुर में नगर निगम में भाजपा ने 91 वार्डो में से 64 वार्डो में सफलता प्राप्त की। कांग्रेस को केवल 18 वार्डो में सफलता मिली, जब विशेष 9 वार्डो में निर्दलीय सफल रहे। इसी प्रकार, जोधपुर में 15 वर्षो के बाद भाजपा ने चुनाव जीते 165 वार्डो में से 39 में विजय प्राप्त की, जब कि कांग्रेस को केवल 19 वार्डो में सफलता मिली। उदयपुर में भाजपा पांचवी बार सत्ता में आ रही है, जबकि कांग्रेस को 55 में केवल 3 वार्डो में सफलता मिली और इस तरह उसे 49 वार्डो में सफलता मिली।

कोटा में नगर निगम में भाजपा ने 65 में से 53 वार्ड जीते। कांग्रेस को केवल छः वार्ड मिल सके। बीकानेर में भाजपा ने 60 वार्डो में से 65 वार्ड जीते जबकि कांग्रेस केवल 16 वार्डो तक सीमित रही। किन्तु भरतपुर नगर निगम में निर्दलियों ने बहुमत प्राप्त किया। शेष 50 नगर परिषदों में से निर्दलियों ने 20 पर जीते प्राप्त की तो भाजपा को 18 में सफलता मिली और कांग्रेस को 11 में। शेष 40 नगर परिषदों और नगरपालिकाओं में, भाजपा 22 में पूर्ण बहुमत मिला और अन्य 22 पर पार्टी अकेली सबसे बड़ी पार्टी बन कर उभरी। मुख्यमंत्री ने अपने बयान में रहा कि मेरे विचार में यह पार्टी कार्यकर्ताओं की विजय है। कांग्रेस को केवल चार में बहुमत मिला, जबकि टोंक और बाड़मेर में कांग्रेस अकेली सबसे बड़ी पार्टी बन कर उभरी। ■

दलित महापंचायत : दिल्ली

हम दलित समाज के साथ सम्बन्ध केवल चुनावी दृष्टिकोण से नहीं बनाते हैं : अमित शाह

भाजपा के समर्थन की घोषणा पर दलित महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा पं. दीनदयाल उपाध्याय द्वारा दिए गए सामाजिक सद्भाव के संदेश को पूरा करते हुए प्रत्येक समुदाय को अपने साथ लेकर चलती है।

अखिल भारतीय दलित महापंचायत ने नई दिल्ली में आयोजित 2 दिसम्बर के एक सम्मेलन में भाजपा को समर्थन देने की घोषणा की। इस महापंचायत में वाल्मीकि समाज से जुड़े लगभग 3000 प्रतिनिधियों ने मोर सिंह की अध्यक्षता में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के सामने भाजपा में शामिल हुए।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं दिल्ली प्रदेश भाजपा प्रभारी श्री प्रभात झा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय और श्री विजय गोयल ने सम्मेलन को सम्बोधित किया और इस अवसर पर त्रिलोकपुरी से स्वतंत्र पार्षद श्री कमल बेनीवाल में भी भाजपा में शामिल हुए।

महापंचायत के अध्यक्ष श्री मोर सिंह ने कहा कि परम्परागत रूप से वाल्मीकि समाज कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रही थी परन्तु वह विडम्बना है कि कांग्रेस पार्टी ने इस समाज को नकारा और आज यह स्थिति है कि हमारे समुदाय के सदस्यों को स्थायी रोजगार प्राप्त नहीं होता है। हमें ठेकेदारी व्यवस्था के अंतर्गत रोजगार मिलते हैं जिसमें हमारे समुदाय के लोगों का शोषण किया जाता है। अत: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सामाजिक उद्धार के कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर वाल्मीकि समाज ने भाजपा का समर्थन करने का निर्णय लिया है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने वाल्मीकि समाज का स्वागत करते हुए कहा कि भाजपा प्रत्येक समुदाय के साथ निस्वार्थ सम्बन्ध स्थापित करना चाहती है। जब हम नए समुदाय के साथ सम्बन्ध बताते हैं तो यह किसी चुनावी लाभ और हानि के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि पं. दीनदयाल उपाध्याय के सामाजिक सद्भाव के संदेश से प्रेरणा लेकर सम्बन्ध बनाते हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि भाजपा दिल्ली प्रदेश वाल्मीकियों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे दलित समाज के लिए लड़ेगी।

भाजपा प्रदेश प्रभारी श्री प्रभात झा ने कहा कि भाजपा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में विश्वास करती है और यह महापंचायत भाजपा को नई ऊर्जा प्रदान करेगी।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय ने महापंचायत में घोषणा की कि भाजपा दिल्ली चुनाव घोषणा पत्र 2015 में पूरे दलित समाज को दो स्पष्ट आश्वासन देती है कि जिसमें सभी कर्मचारियों की सेवाओं की पुष्टि की जाएगी और स्नातकोत्तर अध्ययन करने वाले दलित समाज के सभी बच्चों को लैपटॉप प्रदान करेगी।

श्री उपाध्याय ने कहा कि जल्द ही हम सभी तीन म्युनिसिपल कार्पोरेशनों के सेनीटेशन कर्मचारियों के लिए बिना नकदी वाली बीमा योजना शुरू करेंगे और दिल्ली में सत्ता मिलने के बाद ठेकेदारी व्यवस्था का समाप्त कर देंगे।

इसी प्रकार, हम सीवर सफाई करते समय किसी दुर्घटना में मृत्यु होने पर उस कर्मचारी ने निकट रिश्तेदार की नौकरी दी जाएगी। ■

पृष्ठ 11 का शेष...

तमिल कवि तिरुवल्लुवर जयन्ती प्रतिवर्ष मनाई जाएगी

हमारे संवाददाता द्वारा

केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने सांसद श्री तरुण विजय की इस मांग को तुरंत स्वीकार कर लिया कि तमिल कवि तिरुवल्लुवर की वर्षगांठ उत्तरी भारत के स्कूलों में प्रतिवर्ष मनाई जाएगी और विद्यार्थियों में उनकी शिक्षा को पढ़ाया जाएगा। यह बात उन्होंने राज्यसभा में 28 नवम्बर को कही। शायद संसद के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब तमिल कवि की वर्षगांठ प्रतिवर्ष मनाई जाए और उत्तर भारत के स्कूलों में उनके जीवन और शिक्षा को पढ़ाया जाए। यह मांग उत्तराखण्ड से सांसद श्री तरुण विजय ने की और कहा कि भाषाओं को असहमति के सेतु नहीं बनाना चाहिए और उत्तर भारत को दक्षिणी भाषाओं, विशेष रूप से तमिल को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राचीन भाषाओं में तमिल का महत्वपूर्ण स्थान है और हमें विश्वभर में इसके पद्चिह्न देखने को मिलते हैं तथा यूनेस्को के 'रजिस्टर ऑफ मेमोरी' में तमिल को भारत की पहली भाषा के रूप में चुना गया था।

लगभग पूरे राज्यसभा सदन ने मेज थपथपाते हुए सराहना की। दक्षिण के एआईडीएमके और डीएमके के दलों के नेताओं में श्री ए. नवनीत कृष्णन, कणिमोझी, एस मुथुकुरूप्पम शामिल थे। त्रिची के शिवतरुण विजय के प्रस्ताव का सहर्ष अनुमोदन किया और जेडी(यू) के नेता श्री शरद यादव, पवन वर्मा, एसपी नेता राम गोपाल यादव, टीएमसी और कांग्रेस नेता अहमद हसन, वीरेन्द्र सिंह और ईएम एक के नचियप्पन ने सराहना की। सभी भाजपा सांसदों ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया और श्रीमती स्मृति ईरानी, मानव संसाधन मंत्री ने खड़े होकर राज्य सभा को बताया कि तिरूवल्लुवर की वर्षगांठ सरकारी आदेश द्वारा सभी स्कूलों में मनाई जाएगी।

तिरूवल्लुवर एक विख्यात तमिल संत, कवि और दार्शनिक थे जिनका तमिल साहित्य 'तिरूकुरल, नीति-शास्त्रग्रंथ है। उनका जन्म या तो चेनैई या कन्याकुारी में हुआ था। बौद्ध और शैव दोनों ही उन्हें अपना मानते हैं। समझा जाता है कि तिरूवल्लुवर तीसरी शताब्दी बीसी और पहली शताब्दी बीसी के बीच रहे थे। ■

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को मंजूरी दी है। इसके अलावा बिजली क्षेत्र में कई व्यापक सुधार भी किए हैं।

इस तरह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार ने 'सबका साथ, सबका विकास' नीति पर अमल करते हुए छह महीने से भी कम समय में 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के निर्माण की ठोस शुरुआत की है। आने वाले दिनों में ऐसे ही कई लोक कल्याणकारी उपाय देखने को मिलेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी और उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है।

दूसरी ओर हताश कांग्रेस पार्टी के नेता आजकल अनर्गल राग अलाप रहे हैं। वे राजग सरकार से छह महीने का हिसाब मांग रहे हैं। जिस पार्टी ने 60 साल तक शासन कर देश को तरक्की से वंचित रखा, करोड़ों लोगों को गरीबी में जीने को मजबूर किया, युवाओं के हाथों में बेरोजगारी की हथकड़ियां डाले रखीं, जिसने लोकतंत्र का गला घोंटने की कोशिश की, वही पार्टी आज छह महीने के शासन का हिसाब मांग रही है। ऐसी शोषणकारी, दमनकारी, अलोकतांत्रिक पार्टी को भाजपा के छह माह के शासन का हिसाब मांगने का कोई हक नहीं है। कांग्रेस पार्टी को उसके 60 साल के कुशासन और भ्रष्टाचार की सजा देश की जनता 2014 के लोकसभा चुनाव में और उसके बाद हरियाणा व महाराष्ट्र विधान सभा के चुनाव में दे चुकी है। अब झारखंड और जम्मू कश्मीर की जनता भी कांग्रेस को करारी मात देने को तैयार है। ऐसे में निराशा में डूबे कांग्रेस के नेताओं की मनोदशा को सहज ही समझा जा सकता है। इसी हताशा के चलते कांग्रेस को राजग सरकार की उपलब्धियां नजर नहीं आ रहीं। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी टीम ने मात्र छह महीने में ही असाधारण उपलब्धियां अर्जित की हैं। सरकार जब 60 महीने का अपना रिपोर्ट कार्ड जनता की अदालत में रखेगी तब निश्चित ही उपलब्धियों की फेहरिस्त और लंबी होगी। ■